सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 173, नई दिल्ली, रविवार 31 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सबसे कठिन काम है कार्य करने का निर्णय लेना, बाकी सब केवल दृढ़ता है...

03 संघ प्रमुख मोहन भागवत के शताब्दी संदेशों के सामाजिक-सांस्कृतिक मायने

06 घरेलू खपत और आत्मनिर्भरता की राह

08 उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री का पत्रकार सम्मेलन

राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में,

राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में पीईएफआई (PEFI), युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय गौरव के लिए सवारी।

प्रयागराज से दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और आगरा होते हुए - 24 अगस्त से 31 अगस्त तक,

अमर हॉकी आइकन मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।

आइये विरासत के लिए आगे बढ़ें, आइये भारत के लिए आगे बढ़ें।

हम 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इंडिया गेट पर ग्रैंड फिनाले के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं... हमसे जुड़ें

क्या दिल्ली सरकार की जनहित की बात भी परिवहन आयुक्त को मान्य नहीं, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाए गई याचिका के अनुसार दिल्ली सरकार जनहित में जनता के वाहनों को वाहनों की उम्र समाप्त होने से नहीं अपितु उससे निकलने वाले प्रदूषण के आधार पर वाहनों को स्क्रैप करेगी।

इसी याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किया गया की अगले आदेश तक दिल्ली में किसी भी उम्र पूरे हो चुके वाहनों को ना पकड़ा जाए और ना ही कोई कार्यवाही की जाए।

निष्कर्षः- दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई याचिका का अर्थ हुआ की दिल्ली में कोई भी वाहन डी रजिस्टर नहीं होगा जब तक उस से निकलने वाला प्रदूषण मात्रा से अधिक नहीं पाया जाता जो दिल्ली को प्रदूषित कर रही हो।

पर दिल्ली परिवहन विभाग ने उम्र के आधार पर और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देश के अनुसार डीजल वाहनों को 10 साल पूरे होते ही और अन्य फ्यूल मोड पर चलने वाले वाहनों को 15 साल पूरे होने पर ही डी रजिस्टर कर दिया है।

यहां यह भी जानने योग्य बात है की पूर्व के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में

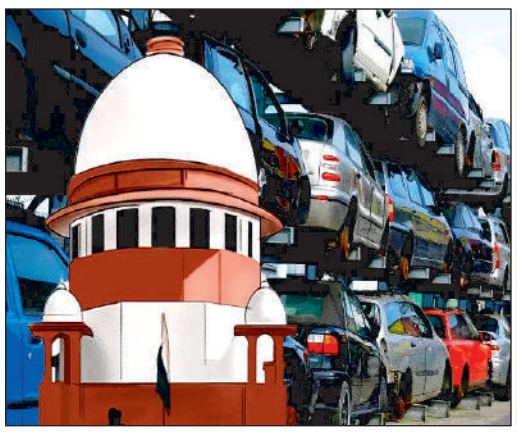

सीएनजी चालित वाहनों पर कोई पाबंदी नही लगाई थी पर दिल्ली परिवहन आयुक्त द्वारा अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ना सिर्फ सीएनजी अपितु समय सीमा बचे हुए ई वाहन भी स्क्रैप हेतु अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सुपुर्द कर दिखाए जो मोटर वाहन नियम के भी खिलाफ था।

इसके अलावा दिल्ली परिवहन आयुक्त ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्विस रुल आर आर, माननीय कैट ओर दिल्ली सरकार के निधि विभाग के दिशा निर्देश को दरकिनार कर तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त कर अपने पद की ताकत को दिखाया

दिल्ली में जनहित में गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर शुरू किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों को बिना पूर्व सूचना और बिना बंद करने के गैजेट नोटिफिकेशन जारी किए अपनी इच्छा से बंद कर दिया

कुल मिलाकर इन सभी से साफ नजर आ रहा है की दिल्ली परिवहन आयुक्त की ताकत दिल्ली सरकार से कही अधिक है क्योंकि ऐसे कार्यों के बाद भी उपराज्यपाल दिल्ली परिवहन आयुक्त से कोई सवाल जवाब तक करना उचित नहीं समझ रहे।

राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण
के तत्वाधान में
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण
नेशनल लोक अदालत
का आयोजन करने जा रही है
शनिवार, 13 सितम्बर, 2025

सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कम्पाउडेबल मामलों के आपसी सुलह से निपटारे हेतु
सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
दिल्ली उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालयों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT), दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली एवं स्थायी लोक अदालत आएँ

लोक अदालत के माध्यम से विवादों का शीघ्र निपटारा एवं सौहार्दपूर्ण समाधान होता है और भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी सुनिश्चित होती है। लोक अदालत में पारित अवार्ड विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इस अवार्ड के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं होती।

- वादी या प्रतिवादी अपने मामलों/चालानों को लोक अदालत में लगवाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं जहां उनके मामले/चालान लंबित है।
- अभी तक जो मामले न्यायालय में दाखिल नहीं हुए है उनके लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय या ई-मेल पर आवेदन 10 सितम्बर 2025 तक दे सकते है।

लोक अदालत में निम्नलिखित श्रेणियों के मामले लिए जाएंगे :-

(i) आपराधिक कम्पाउंडेबल मामले;
(ii) धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत चैक बाउंस के मामले;
(iii) धन वसूली के मामले;
(iv) मोटर दुर्घटना दावा मामले (एमएसीटी);
(v) श्रम विवाद के मामले;
(vi) बिजली और पानी के बिल के मामले;
(vii) वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर);
(viii) भूमि अधिग्रहण के मामले;
(ix) वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले;
(x) राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित);
(xi) अन्य दीवानी मामले;
(xii) कम्पाउंडेबल ट्रैफिक चालान

ट्रैफिक चालान के लिए :-

- इस लोक अदालत में वर्चुअल कोर्ट में 31.05.2025 तक लंबित कम्पाउंडेबल चालान/नोटिस पर विचार किया जाएगा।
- चालान स्लिप डाउनलोड करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका क्यूआर कोड नंबर 1 को स्कैन करके देखी जा सकती है।
- वादी सीधे https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat लिंक के जरिए या क्यूआर कोड नंबर 2 (नीचे दिया गया) को स्कैन करके चालान स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। दिनांक 08.09.2025 से प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से अधिकतम 60,000 चालान/नोटिस डाउनलोड किए जाएंगे, जब तक कि कुल 1.80 लाख चालान की सीमा समाप्त नहीं हो जाती।
- न्यायालय परिसर, न्यायालय संख्या और लोक अदालत का समय, जहां चालान का निपटान किया जा सकता है, चालान पर्ची पर अंकित किया जाएगा और वादी तदनुसार संबंधित न्यायालय परिसर में ही संबंधित न्यायालय संख्या में जा सकते है।

क्यूआर कोड-1 चालान कैसे डाउनलोड करें के लिए स्कैन करें

राजीव बंसल
सदस्य सचिव
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

क्यूआर कोड-2 चालान डाउनलोड के लिए स्कैन करें

(लोक अदालत/डीएसएलएसए कर्मचारी के नाम से धोखाधड़ी कॉल से सावधान रहें। डीएसएलएसए लोक अदालत के लिए कॉल नहीं करता है।)

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें:-
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण
केन्द्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली-110002
फोन: 011-23232124 | ईमेल: lokadalatwing-dslsa@nic.in | वेबसाइट: www.dslsa.org
टोल फ्री हेल्पलाइन न. 1516 (24x7)

टैंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए गूगल फार्म पर क्लिक करें और भरकर जमा करे, पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत अंडर सेक्शन 60), नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एमएसएमई में पंजीकृत
https://docs.google.com/forms/d/18tPL3c_iWxx2SuriV6mYxsske8fCSKbHTLkEH5ynjek/edit

Temple of Liberalization and Welfare Allied Trust
Request for Membership
transportvisheshcontent@gmail.com Switch account
* Indicates required question
Email *
Record transportvisheshcontent@gmail.com as the email to be included with my response
Option 1
Next
Page 1 of 2
Clear

टैंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है—
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
- पुराने कपड़े
- पुराने कंबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
- दशहरे के दूसरे दिन
- दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
- स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

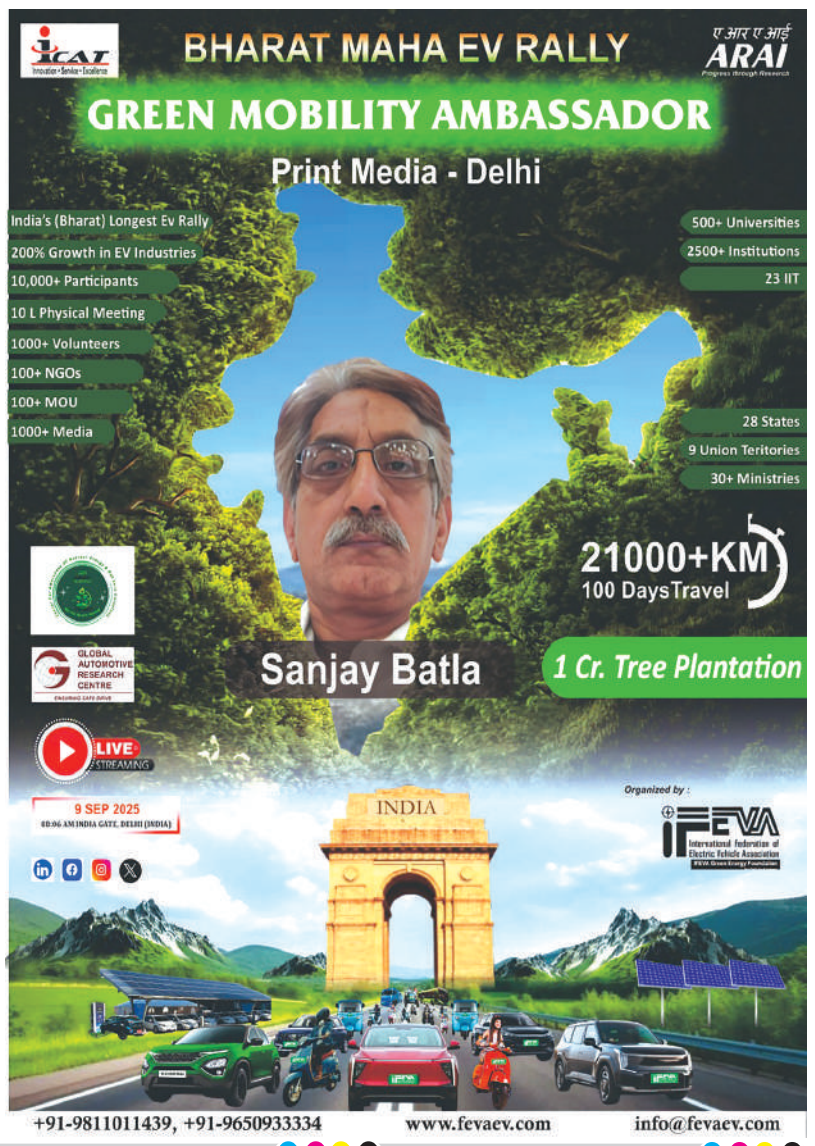

राधा अष्टमी आज

हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल 31 अगस्त 2025 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी को भी बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पर राधी रानी की विधि-विधान से पूजा किया जाता है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस राधा रानी की विशेष पूजा-अर्चना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू सनातन धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। राधा रानी की पूजा-उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विवाहित जीवन खुशहाल रहता है।

राधा अष्टमी का होता है विशेष महत्व

==========

राधा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उनसे भगवान श्री कृष्णा अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में मां लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है।

राधा अष्टमी पर करें ये खास उपाय

==========

राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए। साथ ही राधा रानी और कृष्णजी की विधि-विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन राधाकृपाकटाक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसके साथ ही इस पावन दिन राधा नाम का अधिक से अधिक जाप करें। राधा नाम जपने से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। राधा नाम के जप करने से सभी देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।

राधा अष्टमी पर कैसे करें पूजा ?

==========

* पानी में गंगाजल मिलकर स्नान करें।
* भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का जलाभिषेक करें।
* माता का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें।
* अब राधा जी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें।
* मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें।
* संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें।
* व्रत कथा का पाठ करें।
* श्री राधा चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें।

* पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की आरती करें।
* माता को खीर का भोग लगाएं।
* अंत में क्षमा प्रार्थना करें।

मंत्रः ॐ ह्रीं श्रीराधिकायै नमः।

राधा अष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त

==========

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत- 30 अगस्त को देर रात 10 बजकर 46 मिनट पर

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन- 31 अगस्त को देर रात 12 बजकर 57 मिनट पर

इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा-अर्चना करने का शुभ समय सुबह 11 बजकर 05 मिनट 01 बजकर 38 मिनट तक है।

इन चीजों का करें दान

==========

राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में कभी भी किसी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है।

हमारी आकांशा ही हमें दुःखी करती है। यदि हम सुख की कामना छोड़ दें, तो जगत में कोई भी हमें दुःखी नहीं कर सकता।

यदि कोई प्रतिस्पर्धा में विजयी होने की आकांक्षा छोड़ दे तो जगत में उसको कोई भी हरा नहीं सकता। ध्यान रहे कि शांति को सम्पूर्ण जगत में हम कहीं पर भी खोज लें, शांति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। शांति प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है कि हमारे समक्ष आई इस 'अशांति' को स्वीकार कर लें। स्वीकार का अर्थ यह नहीं है कि हम अशांति को 'ओढ़' लें। जब हम उससे लड़ने रखतें हैं तो वह हमारे चारों तरफ और ज्यादा घनीभूत होने लगती है। यदि हम इस अशांति का निर्विरोध दर्शन करने लगतें हैं तो यही अशांति धुंध की तरह हो जाती है। जैसे-जैसे हम बढ़ते/गुजरते जाते हैं, यही अशांति हमारे लिए मार्ग/रास्ता खोलती/छोड़ती चली जाती है। कदम दर कदम चलते-चलते, उस अशांति में से भी, हमें शांति की राह मिलने लगती है।

बदायूं में झोलाछाप डॉक्टरों का खेल जारी

परिवहन विशेष न्यूज

बदायूं में झोलाछाप डॉक्टरों का खेल जारी। स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही और नोडल डॉक्टर नितिन यादव की कथित मिलीभगत के चलते जिले में झोलाछाप डॉक्टर और अवैध नर्सिंग होम खुलेआम संचालित हो रहे हैं। जिला अधिकारी के आदेश के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से मरीजों की जान जोखिम में है। सूत्रों के अनुसार, जिलेभर में हजारों झोलाछाप डॉक्टर और सैकड़ों अवैध नर्सिंग होम ऐसे हैं, जहां बिना डिग्री वाले लोग गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। नोटिस और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उगाही का सिलसिला चल रहा है। भ्रष्टाचार और आर्थिक समझौतों के कारण कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की नाकामी पर नाराज हैं और इस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे.

प्रेम पच्चीसा (भाग 16)

राजेन्द्र रंजन गायकवाड़
सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रोहन, माया, और मालती शहर के एक बड़े एनजीओ के दफ्तर में प्रवेश करते हैं। वहाँ का माहौल गर्मजोशी और समर्पण से भरा है। दीवारों पर महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की कहानियों के पोस्टर लगे हैं। एनजीओ की संचालिका, सुधा जी, उनका स्वागत करती हैं। सुधा जी, एक दयालु और प्रेरणादायक महिला, उन्हें एनजीओ के कामकाज के बारे में बताती हैं। वह बताती हैं कि यह एनजीओ असहाय, गरीब, और परित्यक्त महिलाओं को न केवल आश्रय देता है, बल्कि उन्हें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, और रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। रोहन उत्सुकता से पूछता है, ₹आप इतने सारे लोगों की मदद कैसे कर पाते हैं?₹

सुधा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ₹समुदाय का सहयोग और हमारे स्टाफ की मेहनत हमें यह संभव बनाती है।₹ माया, जो खुद एक सामाजिक संस्था बनना चाहती है, सुधा जी से पूछती है, ₹क्या हम भी यहाँ सदस्य बन सकते हैं?₹ सुधा जी खुशी से कहती हैं, ₹बिल्कुल! हमें हमेशा उत्साही और समर्पित युवाओं की जरूरत होती है।₹

हम सब मिलकर समाज कर सकते हैं। दूसरे कोने में मालती जो थोड़ी शांत स्वभाव की हैं, चुपके से हाल में बैठी महिलाओं को सिलाई मशीन पर काम करते देखती हैं। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक नोटिस करती है।

सुधा जी उन्हें एक प्रशिक्षण कक्ष में ले जाती हैं जहाँ कुछ महिलाएँ सिलाई, बुनाई, और कम्प्यूटर कोर्स सीख रही हैं। एक महिला, राधा, अपनी कहानी साझा करती है। वह बताती है कि कैसे वह अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद इस एनजीओ में आई और अब वह एक छोटा सा सिलाई का व्यवसाय चला रही है। उसकी कहानी सुनकर माया और मालती की आँखें नम हो जाती हैं, जबकि रोहन गहरी सोच में पड़ जाता है।

सुधा जी उन्हें एक छोटा सा कार्य सौंपती हैं अगले हफ्ते होने वाले एक जागरूकता शिविर की योजना बनाने में मदद करना। रोहन तुरंत कहता है, ₹हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे!₹ माया और मालती भी उत्साह से सहमत होती हैं।

ज़िंदगी यहाँ से कैसे आगे बढ़ती है?

रोहन, माया, और मालती शिविर की तैयारी में कुछ अनोखा करना चाहते हैं।

क्या वे एक नई महिला अनीता की कहानी सुनते हैं जो जेल से रिहा हुई लेकिन उसके परिवार वाले उसे सज़ा पूरी होने बाद अपराधी मानते हैं। तब जेल अधीक्षक , पहले ईश्वरीय विश्व विद्यालय की बहिन जी बात करते हैं तो एक रात विद्या नहीं जी उसे आश्रय देती हैं। लेकिन दूसरे दिन वो जेल अधीक्षक की बताती हैं कि संस्था में रिहा कैदी महिला नहीं रख सकते । तब सुधा जी के पास अनीता को सुरक्षित भेजा जाता है। कुछ दिन बाद अनीता कहती है उनकी एक लड़की जबलपुर में रहती वो उसके पास रहेगी ? इधर भी जेल अधीक्षक यथासंभव करके अनीता को जबलपुर पूरी सुरक्षा के साथ भेजते हैं।

अनीता की बेटी क़ैद से आई मां देखकर बहुत उल्टा - सीधा बोलती है, यहां तक महिला सुरक्षा कर्मी को भी गली गलौज करती है। अब सुरक्षा स्टाफ के सामने अप्रत्याशित चुनौती आती है, कि अनीता को कहां ले जाएं?

(भाग 17)

मद्रास हाईकोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार

मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिरों के लिए है, सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। 80 करोड़ रुपये मंदिर निधि से

27 मैरिज हॉल बनाने की योजना रद्द

कोर्ट ने कहा— ये गैरकानूनी और दुरुपयोग है

मंदिर की संपत्ति सरकार की नहीं, श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है। हर बार की नौटंकी बहुत बार कोर्ट ने फटकार लगाई है।

ज़िंदगी और ख़यालात का सफ़र।

ज़िंदगी एक आईना है, और उसका नक्शा हमारे ख़यालात बनाते हैं। इंसान जैसा सोचता है, वैसे ही मंज़र उसके सामने उभर आते हैं। अगर दिल में उम्मीद के चराग़ जल उठें तो अंधेरी रातें भी रोशन हो जाती हैं, और अगर सोच में रोशनी है तो अंधेरे भी रोशन बनने लगते है। लेकिन जब ज़हन नकारात्मक ग़ुबार से भर जाए तो आसमान के सितारे भी धुंधले पड़ जाते हैं और रोशनी भी बोझ मालूम होने लगती है।ख़यालात की हैसियत बीज जैसी है। मोहब्बत, और शुक्रगुजारी के बीज अगर दिल की ज़मीन में बो दिए जाएँ तो ज़िंदगी रंग-ब-रंग फूलों से महक उठती है। वहीं शक्क, कीना और बदगुमानी के बीज कांटों का जंगल उगा देते हैं, जो इंसान के हर क़दम को दर्द और अज़ीयत से भर देते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है— इंसान की तक़दीर उसके ख़यालात के हवाले होती है।रोशन-ख़याल शख़्स तारीकी में चराग़ ढूंढ लेता है, जबकि तंग-नज़र इंसान उजाले में भी अंधेरे तलाश करता है। सक़ल्प की रोशनी ही इंसान का असली सहारा है। अगर सोच बुलंद और पाक हो तो नफ़रतें भी मिट सकती हैं और ज़िंदगी एक गुलिस्तान का रूप ले सकती है।

हर इंसान, को अपने ज़हन को तंगदिली से निकालकर उम्मीद और मोहब्बत के आसमान पर उड़ने देने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के लिए आसानी पैदा करते रहना चाहिए। और मुश्किलात को सब्र और हिम्मत से गले लगाना चाहिए देख, यही ख़याल ज़िंदगी को जन्नत बना देंगे और यही तुझे कामयाबी की बुलंद चोटियों तक पहुँचा देंगे।

डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह

सनातन धर्म कितना पुराना ?

550 साल पहले गुरुनानक देव जी हुए!

627 साल पहले कबीरदास जी पैदा हुए ! 1455 साल पहले हजरत मुहम्मद पैदा हुए!

2007 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुए!

2267 साल पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए भारत में!

2400 वर्ष पहले जगद्गुरु आदि शंकराचार्य हुए!

2588 साल पहले बुद्ध पैदा हुए नेपाल।

(भारत)में!

2624 साल पहले महावीर स्वामी बुद्ध से पहले पैदा हुए!(जैनियों के 24 वें नम्बर के तीर्थंकर)

3700 साल पहले हजरत मूसा पैदा हुए!

यहुदियों- ईसाईयों- मुस्लिमों का पहला पैगम्बर इब्राहिम पैदा हुए ईसा मसीह से 2000 साल पहले मतलब आज से 4085 वर्ष पहले। इससे पहले आदम और हव्वा पैदा हुए 5000 साल पहले क्योंकि इस्लाम और बाईबिल के अनुसार धरती 6000 साल पहले बनी है! (इससे पहले इनके पूर्वज भी सनातनी ही थे)

इनसे पहले ऋषभदेव जी थे आज से 10,000 वर्ष पहले! (एसा कुछ जैनियों का मत है, किंतु जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी इक्ष्वाकुवंशीय थे और उनका जन्म सतयुग में श्रीराम चंद्र से बहुत पहले हो चुके थे और उनकी ऊंचाई लगभग 21 फीट थी।)

महाभारत का युद्ध हुआ आज से 5092 वर्ष पूर्व जब श्रीकृष्ण नें गीता का उपदेश दिया था!

महाभारत के युद्ध से पहले श्रीकृष्ण का जन्म हुआ लगभग आज से 6000 वर्ष पहले !!!

(द्वापर के अन्त में)

महाराजा यदु का जन्म हुआ श्री कृष्ण से बहुत पहले जिनसे यदु वंश चला!

त्रेतायुग के मध्य में आज से लगभग 14 लाख साल पहले श्री राम हुए!

तब श्रीराम और चारों भाइयों की ऊंचाई लगभग 17 फीट थी!

श्री राम से पहले उनके पिता दशरथ और दादा अज का जन्म हुआ!

14 लाख साल पहले तक वेदों की सारी ऋचाएं लिखी जा चुकी थी!

राजा अज से पहले राजा भागीरथी पैदा हुए जिन्होनें अपने शत्रु को ही अपना राजपाठ दान में दे दिया था आत्मज्ञान की खोज के लिए!

राजा भगीरथ से पहले राजा सगर पैदा हुए!

राजा सगर से पहले सतयुग में राजा पृथु हुए 21 लाख साल पहले जिनसे धरती का नाम पृथ्वी पडा--

राजा पृथु से पहले वेन हुए!

सतयुग के प्रारम्भ में!

पृथु और वेन से पहले इक्ष्वाकु हुए !

उनसे पहले सप्त ऋषि और प्रजा पालक राजा मनु हुए!

जो मनु हुए वों 7 वें मनु वैवस्वत हैं!

7 वें मनु का यह 28 वां चतुर्युग चल रहा है!

इनसे पहले इसी पृथ्वी में 6 बार मनु और उनकी प्रजाएं उत्पन्न और नष्ट हो चुकी हैं!

7 मनु और उनकी प्रजाएं अभी और होने हैं और उसके बाद पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा!

7 मनु से पहले विवस्वान(सूर्य) हुए!

हिमालय पर्वत 7 बार बन चुका है!

विवस्वान से पहले कश्यप हुए!

कश्यप से पहले मरीची हुए! ब्रह्मा जी के पुत्र नारद और प्रजापति दक्ष आदि हुए!

ब्रह्मा जी से ही वासिष्ठ - क्रतु- अंगिरा आदि ऋषि उत्पन्न हुए !

इनसे पहले ब्रह्मा जी नें ८ वसु(पृथ्वी- सूर्य- चंद्र- नक्षत्र- अग्नि- जल- वायु -आकाश) ११ रुद्र और १२ आदित्य इंद्र अश्विनि कुमार आदि ** प्रकार के देवताओं को उत्पन्न किया!

ब्रह्मा जी अपनें हर नये कल्प में नये ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं!

ब्रह्मा जी अपने एक दिन में एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जिसे कल्प कहते हैं!

कल्प के पूर्ण होने पर कल्पान्त प्रलय होती है!

ब्रह्मा जी के जीवन में अनेक कल्प होते हैं और अन्त में ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, जिसे परार्ध कहते हैं, उस समय परार्ध प्रलय होली है!

क्योंकि यह ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी की कल्पना से उत्पन्न होता है, इसलिए ब्रह्मांड की आयु अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है!

इनसे पहले स्वयं कमल योनि ब्रह्मा जी श्री विष्णु के नाभि कमल से क्षीर(दूध की तरह निर्मल) सागर में पैदा हुए!

हमारे ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में 14 लोक हैं!

स्मरण रहे विष्णु का बैकुंठ ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड के 14 लोकों से परे है!

विष्णु के गर्भ से निकले नाभि कमल के कारण ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है!

उनसे पहले परम शिव और परम शक्ति के भीतर त्रिदेव और उनकी देवियां अव्यक्त रूप में रहते थे!

एसे ना जाने कितने ब्रह्मांड शिव- शक्ति के विलास के संयोग से ब्रह्मा जी अपनें हर कल्प में बनाते हैं!

सनातन धर्म को जानों--

योग वासिष्ठ पढ़ो--

क्योंकि ब्रह्मा जी नें ब्रह्म ऋषि वासिष्ठ की उत्पत्ति इसीलिए की थी ताकि वे कलियुग की शांति के लिए योग वासिष्ठ का ज्ञान श्रीराम जी को दें!

सृष्टियां अनादि काल से उत्पन्न और नष्ट हो रही हैं!

मूर्ख मनुष्य केवल अपनें अहंकार और अल्पबुद्धि के कारण आपस में लड- मर रहे हैं!

अपनी आत्मा में परमात्मा को खोजो यही सनातन ज्ञान है!

सनातन धर्म और ज्ञान तो सृष्टि के पहले से और सृष्टि के साथ साथ सदा से है!

पूर्ण परमात्मा से जो कुछ उत्पन्न हुआ है, वह भी पूर्ण ही है।

परमात्मा सभी जीवों की आत्मा का भी आत्मा है, सभी के भीतर और बाहर वही प्रकाशित हो रहा है,

अज्ञानता के कारण ही सभी प्राणि आपस में तर्क वितर्क और द्वंद्व करते हैं!

अज्ञानता का नाश करके अपने पूर्ण स्वरूप में समाहित हो जाना ही सनातन है!

***हर हर महाकाल**

फ्री ऑफर का जादू: लोग मुफ्त में कंघी भी ले लेंगे भले गंजे हों

संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल

[लेखक पिछले 18 वर्षों से वाणिज्य-अर्थशास्त्र के शिक्षक, वित्तीय एवं कर सलाहकार हैं]

"मुफ्त की चीज़ पर दिल फिदा,
जेब खाली हो जाए तो क्या हुआ।"

आज के उपभोक्ता व्यवहार को अगर एक लाइन में समझाना हो तो यही कहा जा सकता है कि "Free" शब्द सुनते ही आदमी की सोच का गणित बदल जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के सबसे पुराने और सबसे कारगर हथियारों में से एक है फ्री ऑफर। यह सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। ग्राहक को भले ही उस चीज़ की ज़रूरत न हो, लेकिन मुफ्त में मिल रही है तो उसे अपनाने की संभावना लगभग सौ प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

सोचिए, गली—मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े होकर अगर कोई कहे कि "फ्री सैंपल है, लीजिए" — तो क्या आप बिना देखे निकल जाएंगे? शायद नहीं। भले ही आपको उसकी ज़रूरत न हो, लेकिन दिमाग कहेगा — "चलो रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगा।" यही है वह जादू जो फ्री ऑफर पैदा करता है।

मनोविज्ञानियों का मानना है कि जब इंसान को कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो उसके दिमाग में "रिस्क अलार्म" का अलार्म बजता है। मतलब उसे लगता है कि कोई घाटा नहीं है, बस फायदा ही फायदा है। और यहीं से कंपनियां उपभोक्ता की इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती हैं।

भारत में ही देख लीजिए। मिठाई की दुकान हो या मोबाइल रिचार्ज, हर जगह "एक के साथ एक फ्री" का बोर्ड टंगा होता है। त्योहारों के सीज़न में तो जैसे "फ्री ऑफर" का बाढ़ आ जाता है — साबुन के साथ डिब्बा, बिस्कुट के पैकेट के साथ कप और टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश। मज़े की बात यह है कि ग्राहक अक्सर मूल चीज़ की क्वालिटी या कीमत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि "कम से कम कुछ तो फ्री में मिल रहा है।"

फ्री ऑफर का यह जादू सिर्फ छोटे-मोटे सामान तक सीमित नहीं है। बड़े-बड़े ब्रांड भी इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। कार कंपनियां गाड़ी खरीदने पर मुफ्त सर्विस देती हैं, मोबाइल कंपनियां डाटा पैक पर मुफ्त एसएमएस देती हैं और ई-कॉमर्स कंपनियां तो "फ्री डिलीवरी" के नाम पर पूरा मार्केट जीत चुकी हैं। "फ्री डिलीवरी" असल में मुफ्त नहीं होती, उसका खर्च प्रोडक्ट की कीमत में पहले ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन ग्राहक के दिमाग में यह अहसास बैठ जाता है कि उसे कुछ फायदा हो रहा है। यहाँ तक कि डिजिटल युग में तो "फ्री" का जादू और भी गहरा हो गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल — ये सब अपने आप में मुफ्त सेवाएँ हैं। कोई इनसे पैसा नहीं लेता, लेकिन इसके बदले कंपनियां हमारे डेटा और ध्यान का कारोबार करती हैं। यानी असली कीमत हमसे ली जाती है, लेकिन हमें लगता है कि सबकुछ मुफ्त है। यही तो आधुनिक मार्केटिंग की सबसे बड़ी चाल है।

अगर इतिहास में जाएँ तो मुफ्त ऑफर का कांसेप्ट नया नहीं है। पुराने समय में भी हाट-बाजारों में दुकानदार मुफ्त में थोड़ी मात्रा में चीज़ चखने के लिए देते थे। जैसे मसाले बेचने वाला थोड़ा सा मसाला हाथ में रख देता था, ताकि ग्राहक उसकी खुशबू महसूस करके खरीद ले। मिठाई वाला ग्राहक को 'टेस्टिंग' के नाम पर छोटा टुकड़ा दे देता था। उस जमाने में इसे "मुफ्त चखना" कहते थे, आज इसे आधुनिक भाषा में "सैंपलिंग स्ट्रैटेजी" कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह स्थानीय स्तर पर होता था, अब यह एक ग्लोबल मार्केटिंग टूल बन चुका है। आज के जमाने में ग्राहक खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। वह सोचते हैं कि वह कंपनी की चाल को समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केटिंग वालों का गणित हमेशा एक कदम आगे होता है। जब आप "एक के साथ एक फ्री" में प्रोडक्ट लेते हैं, तो अक्सर आपने उतना ही खर्च किया होता है जितना दोनों पर अलग-अलग करने पड़ता। कंपनियों को घाटा नहीं होता, बल्कि बिक्री बढ़ जाती है। मजेदार बात यह है कि मुफ्त ऑफर से ग्राहकों में "खुशी का हार्मोन" भी एक्टिव हो जाता है। रिसर्च बताती है कि फ्री चीज़ मिलने पर इंसान के दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है, जो वैसा ही अहसास देता है जैसा लॉटरी जीतने या गिफ्ट मिलने पर होता है। यानी यह सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं बल्कि भावनात्मक संतुष्टि भी देता है। त्योहारों का उदाहरण लीजिए। दिवाली, होली, ईद या क्रिसमस — हर त्योहार में उपभोक्ता का मूड खर्च करने का होता है। ऐसे समय पर कंपनियां "फ्री ऑफर" को हथियार बनाकर खरीदारी को और बढ़ा देती हैं। ग्राहक जब गिफ्ट पैक या बोनस आइटम देखकर खरीदता है तो उसे लगता है कि उसने "स्मार्ट डिसीज़न" लिया है, लेकिन असल में वह मार्केटिंग के जाल में फंस चुका होता है। फ्री ऑफर का असर इतना गहरा है कि कई बार लोग उस प्रोडक्ट को भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं। मान लीजिए किसी दुकान पर साबुन के साथ कटोरी फ्री मिल रही है। अब अगर ग्राहक के घर में पहले से ही पर्याप्त साबुन है, फिर भी वह अतिरिक्त साबुन खरीद लेगा सिर्फ उस कटोरी के लालच में। यही मनोविज्ञान कंपनियों के बिज़नेस मॉडल को मज़बूत करता है।

ऑनलाइन दुनिया में भी यही पैटर्न है। कई ऐप "फ्री ट्रायल" का विकल्प देते हैं। एक महीने मुफ्त में इस्तेमाल कीजिए और फिर सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। लोग पहले तो खुशी-खुशी "फ्री" का फायदा उठाते हैं, लेकिन बाद में जब ऑटो-डिडक्शन होता है तो पता चलता है कि मुफ्त में लिया गया ऑफर असल में कितना महंगा पड़ा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या यह फ्री ऑफर हमेशा ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा होता है? इसका जवाब है — नहीं। कई बार मुफ्त ऑफर की वजह से लोग अपनी वास्तविक ज़रूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ग्राहक "ज़रूरत" और "लालच" में फर्क समझे। दूसरी तरफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो यह रणनीति सबसे सफल है। यह न सिर्फ बिक्री बढ़ाती है, बल्कि ब्रांड की पहचान भी मजबूत करती है। ग्राहक जब बार-बार मुफ्त में प्रोडक्ट या सेवा अनुभव करता है, तो उसके मन में उस ब्रांड के प्रति भरोसा बढ़ता है। यही कारण है कि आज लगभग हर इंडस्ट्री — चाहे वह FMCG हो, टेक्नोलॉजी हो, या सर्विस सेक्टर — फ्री ऑफर को अपनी मार्केटिंग का अहम हिस्सा मानती है।

भविष्य में यह ट्रेंड और भी बढ़ने वाला है। Artificial Intelligence और Data Analytics के ज़माने में कंपनियां ग्राहकों की पसंद-नापसंद को इतनी बारीकी से समझ पाएंगी कि हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग पर्सनलाइज्ड "फ्री ऑफर" डिज़ाइन किए जाएंगे। यानी गंजे को कंघी मुफ्त में नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए शायद शेविंग क्रीम या टोपी फ्री होगी।

संघ प्रमुख मोहन भागवत के शताब्दी संदेशों के सामाजिक-सांस्कृतिक मायने

कमलेश पांडेय

देश दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अगले एक वर्ष तक विभिन्न प्रबुद्ध कार्यक्रम व अभियान चलाने वाला है ताकि भारतीय सभ्यता-संस्कृति पर आधारित हिन्दू राष्ट्र के व्यापक दर्शन और उसमें अंतर्निहित महान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जनसरोकारों से जन-जन को परिचित कराया जा सके।

इस नजरिए से नई दिल्ली के प्रतिष्ठित विज्ञान भवन सभागार में अपने कर्मठ समाजसेवी लोगों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा, उन शताब्दी संदेशों के सामाजिक-सांस्कृतिक मायने को समझने-समझाने की जरूरत है ताकि भव्य व मजबूत भारत का पुनरूत्थान संभव हो सके। यही बात शेष दुनिया पर भी लागू हो सकती है। इसलिए उन पर न केवल भारत सरकार बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष को भी गौर करना चाहिए और अपनी प्रशासनिक नीतियों में उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए।

दरअसल, संघप्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ कहा और भारत के समग्र हित में जो कुछ नहीं कह पाए, उसे समझने-समझाने की जरूरत है। उनके उर्वर लोक दर्शन को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि सबका भला हो सके। आप मानें या न मानें, उनकी इन बातों में दम है कि उपभोक्तावाद की वृद्धि के कारण दुनिया में पाप, दुःख और संघर्ष बढ़ रहा है। इसलिए जनसेवा और त्याग जैसे धार्मिक संस्कारों से ही उनका सम्यक मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि वोक कल्चर पूरी दुनिया पर छा रहा संकट है क्योंकि लोग अपने अलावा किसी दूसरे की ओर नहीं देख रहे हैं। इससे बचने के लिए लोगों को केवल धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए।

मोहन भागवत ने 'हिंदुत्व' की परिभाषा पर भी विस्तार से बात करते हुए समझाया कि, हिंदुत्व या हिंदुपन क्या है? अगर इसे संक्षेप में कहना हो तो दो शब्द हैं सत्य और प्रेम। दुनिया का संचालन एकता से होता है, सौदेबाजी और अनुबंधों से नहीं। चूंकि हिंदुस्तान का जीवन मिशन विश्व कल्याण है। उनका कहना था कि विकास की दौड़ में दुनिया ने भीतर झांकना छोड़ दिया है। अगर भीतर खोज होगी तो ऐसी अनंत खुशी मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे ही पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुत्व किसी एक संप्रदाय या समुदाय की विचारधारा नहीं है, बल्कि यह वह सोच है जो सत्य और प्रेम पर आधारित होकर सबको साथ लेकर चलती है। अगर यही मार्ग अपनाया जाए तो दुनिया के संघर्ष खत्म हो जाएंगे और सच्चा सुख-शांति स्थापित होगी।

लिहाजा, सम्भव है कि भागवत के सम्पूर्ण शताब्दी उपदेश का भविष्य में कुछ सकारात्मक असर हो सकता है।

पहला, भाजपा-विरोधी दलों का आरोप कमजोर हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ सत्ता हथियाने का औजार है जबकि भाजपा की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास है। दूसरा, भाजपा को अपनी भाषा और नीतियों में "समावेशिता" दिखानी पड़ सकती है। इससे उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी उसका विस्तार संभव है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश भी जाएगा कि भारत का राष्ट्रवाद अधिनायकवादी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और समावेशी है। इसमें ग्लोबल साउथ का भी हित निहित है जो कि दलित-पिछड़े देशों का समूह है।

सामाजिक विविधता और उससे संघर्ष की आशंका पर सवाल उठते हुए मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि समाज में जीवन में विविधता है लेकिन कई बार इनमें संघर्ष भी दिखाई देता है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है और इसके लिए सबके बीच समन्वय स्थापित करना है। इसके लिए कई बार कुछ त्याग भी करना पड़ता है जिसके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म सदैव सार्वकालिक सुखदाई होता है। यदि कोई वस्तु दुखदाई है तो वह धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मरने के बाद अलग-अलग वर्गों के लिए अलग श्मशान होने की सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सबको साथ लेकर देश को मजबूत बनाएंगे।

बढ़ते उपभोक्तावाद पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्तावाद की वृद्धि के कारण दुनिया में पाप, दुःख और संघर्ष बढ़ रहा है। वोक कल्चर पूरी दुनिया पर छा रहा संकट है। क्योंकि लोग अपने अलावा किसी दूसरे की ओर नहीं देख रहे हैं। इससे बचने के लिए लोगों को केवल धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। यह धर्म लोगों को हमेशा मध्यम मार्ग पर बनाए रखता है और इससे आपस में संघर्ष पैदा नहीं होता। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शब्दों में दोहराया कि, भारत के पास धर्म है जिसे उसे समय-समय पर दुनिया को देनी चाहिए। धर्म शाश्वत है। उन्होंने कहा कि धर्म मूल तत्व है जो स्वभाव होता है। इसका धर्मांतरण नहीं किया जा सकता।

आरएसएस के जनोपयोगी सोच को जन जन तक पहुंचाने की बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस का लक्ष्य यह है कि जो संघ में हो रहा है, वह परिवार और समाज में भी हो। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि समाचारों की दुनिया से भारत को नहीं समझा जा सकता। समाचारों में जितना गलत दिखाई देता है, उससे 40 गुना अधिक अच्छा समाज के बीच हो रहा है। इसलिए समाज को संगठित करने के लिए जातिगत भेदभाव को यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिए। इसके लिए स्वयंसेवकों को अपने आसपास की बस्तियों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब तक समाज में आपसी अविश्वास और भेदभाव हो, उसे समाप्त किए बिना संबंध मजबूत नहीं हो सकता।

समाज के पददलितों की चिंता को स्वर देते हुए भागवत ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों का सहयोग एक स्वाभाविक कार्य हो जाना चाहिए। पारस्परिक दूरियों को पाटने के लिए दोनों वर्गों से काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास और संस्कृति एक ही है। केवल नक्शे पर रेखाएं खिंचने से नए-नए देश बन गए हैं, लेकिन पूर्व में उनकी संस्कृति भी एक ही रही है। दूसरे देशों को जोड़ने का कार्य सबसे पहले पड़ोसी देशों से शुरू होना चाहिए। उनके साथ भी आत्मीय संबंध बनाकर उनके विकास की भी चिंता होनी चाहिए।

युवाओं को लक्षित करते हुए मोहन भागवत ने ठीक ही कहा है कि आज युवाओं की सोच निजी स्तर पर केंद्रित होती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इसे ठीक करना है तो इसके लिए कुटुंब प्रबोधन करना चाहिए। इसके अंतर्गत सप्ताह में एक बार एक समय पर बैठकर भोजन करना और अपनी धर्म-संस्कृति पर चर्चा करनी चाहिए। इस बैठक में यह भी चिंता करनी चाहिए कि जिस धर्म और समाज से हम हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक समरसता के लिए परिवारों को आपस में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मरने के बाद श्मशान का भेद समाज के लिए सही नहीं है।

उन्होंने ठीक ही कहा कि अपने घर में भोजन, भजन, वस्त्र सब कुछ अपनी परंपरा के अनुसार होना चाहिए। युवाओं का आह्वान करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसात्मक तरीका नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग करके लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं।

'...अगर ऐसा हो तो मैं आरएसएस के खिलाफ नहीं'; छह साल बाद फिर भागवत से मिलने जाएंगे मदनी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जल्द ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे। जमीयत की बैठक में भागवत की गलतफहमी दूर करने की अपील का स्वागत किया गया। मदनी ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम एकता की पहल जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। जमीयत ने देश में सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर चिंता व्यक्त की साथ ही असम में मुस्लिम परिवारों के निष्कासन का मुद्दा उठाया।

नई दिल्ली। शताब्दी वर्ष के लक्ष्यों में हिंदू-मुस्लिम एकता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोर के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दोनों पक्षों से गलतफमियों के दूर करने के आग्रह से माहौल बदलता दिख रहा है।

देश में मुस्लिम समाज के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक में मोहन भागवत की अपील पर विस्तार से चर्चा हुई है।

जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत करते हुए कहा कि इस दिशा में पहल होनी चाहिए तथा यह जमीन पर भी दिखना चाहिए। अगर हिंदू-मुस्लिम के साथ आने की बात हो, तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ नहीं हैं।

बैठक में मौजूद एक पदाधिकारी के अनुसार, मदनी ने जोर दिया कि दोनों के बीच गलतफमियों को दूर करने का प्रयास बयानों से आगे कृत्यों में भी आना चाहिए। असम सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के घरों को गिराने जैसी घटनाओं पर भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आए।

वैसे, बैठक में जमीयत के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि मदनी के नेतृत्व में जमीयत का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने मोहन भागवत से मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात अगले माह सितंबर में संभव है।

वैसे यह पहली बार नहीं होगा जब भागवत व मदनी मिलेंगे। इसके पूर्व छह वर्ष पहले भागवत के बुलावे पर मदनी उनसे मिलने पहुंचे थे। वर्ष 2019 में तब यह मुलाकात उदासीन आश्रम में संघ के अस्थायी कार्यालय में हुई थी। जिसमें आपसी भाईचारे के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया था।

संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विज्ञान भवन में तीन दिवसीय संघ के 100 वर्ष-नए क्षितिज संवाद कार्यक्रम में मोहन भागवत ने हिंदू-मुस्लिम के बीच अविश्वास के माहौल को दूर करने की अपील की है।

मौजूदा हालात पर जमीयत ने जताई चिंता

जमीयत की कार्यकारी की बैठक में आरोप लगाया गया कि देश में सांप्रदायिकता, कट्टरता और अशांति बढ़ रही है। अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव तथा मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है।

खासतौर पर असम में जारी निष्कासन और पचास हजार से अधिक मुस्लिम परिवारों को केवल धर्म के आधार पर बेघर किया गया। अरशद मदनी ने असम मामले में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की अपील की। गाजा में वहां के निवासियों पर भी चिंता व्यक्त की गई।

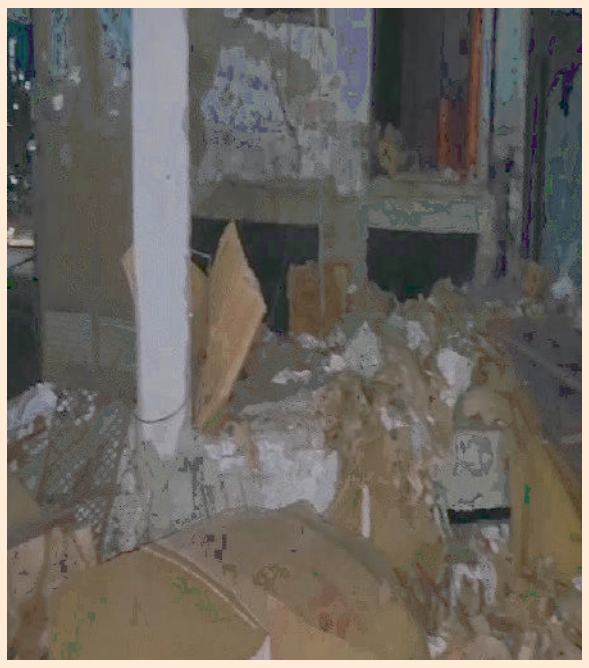

दिल्ली के बवाना में धमाके के बाद फैक्ट्री का हिस्सा गिरा, हादसे में एक की मौत और दो घायल

बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक मैटल कोटिंग फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ जिससे इमारत का हिस्सा ढह गया। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक के बेटे की मृत्यु हो गई और दो लोग घायल हो गए। धमाका इतना शक्तिशाली था कि तीन मंजिला इमारत का भूतल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में यह सिलेंडर या कंप्रेसर विस्फोट का मामला लगता है।

बाहरी दिल्ली। बवाना औद्योगिक क्षेत्र में तेज धमाके के बाद मैटल कोटेड (रैक कोटिंग) फैक्ट्री की इमारत का हिस्सा ढह गया। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक के बेटे की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि तीन मंजिला इमारत के भूतल का अगला हिस्सा पूरी तरह से ढह गया और दूसरी मंजिल को भी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री से कुछ दूरी पर सड़क किनारे सैलून चला रहा युवक भी मलबे की चपेट में आने से जख्मी हो गया।

दो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह सिलेंडर या कंप्रेसर विस्फोट का मामला प्रतीत होता है। राहत एवं बचाव के लिए दमकल की छह गाड़ियों मौके पर भेजी गईं।

यह हादसा शनिवार शाम साढ़े के करीब बवाना स्थित डीएसआइडीसी सेक्टर-एक के प्लाट संख्या 86 में हुआ।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में सिलेंडर या कंप्रेसर में विस्फोट की सूचना बवाना पुलिस को मिली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शेरकोट गांव के रहने वाले नाजिम (35) बेहोशी की हालत में पाए गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के देबौदा गांव निवासी अखिलेश (22) को भी मामूली चोटें आईं और अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि इस फैक्ट्री में रैक कोटिंग होती थी। फैक्ट्री को दिल्ली के न्यू मुल्तान नगर (पश्चिम विहार) के रहने वाले निज़ामुद्दीन चलाते हैं। निजामुद्दीन ने इमारत को किराए पर ले रखा था। निजामुद्दीन मृतक युवक नाजिम के पिता हैं।

उन्होंने बताया कि विस्फोट कहां और किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। आरंभिक जांच में यह सिलेंडर या कंप्रेसर विस्फोट का मामला प्रतीत होता है। इस मामले में बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दमकल विभाग की ओर से बताया गया कि शाम 6:37 बजे हादसे की सूचना मिली थी। राहत एवं बचाय कार्य के लिए छह गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। बताया जाता है कि विस्फोट के बाद फैक्ट्री के कुछ हिस्से में आग भी लग गई थी।

पीछे के दरवाजे से राजधानी में बिजली महंगी करने की तैयारी, डीईआरसी पर डिस्कॉम को लाभ पहुंचाने का आरोप

दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को पीपीएसी वसूलने का अधिकार देने का विरोध हो रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। डीईआरसी में चेयरमैन का पद खाली होने से भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि डिस्काम को मनमानी करने की छूट दी जा रही है और उपभोक्ताओं को राहत देने की बजाय बिजली कंपनियों का पक्ष लिया जा रहा है।

नई दिल्ली। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बिजली खरीद समायोजन शुल्क (पीपीएसी) वसूलने का अधिकार दिए जाने की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका विरोध शुरू हो गया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस कदम से डिस्कॉम की मनमानी बढ़ेगी। पहले से ही उपभोक्ताओं से कई तरह के अधिभार वसूले जा रहे हैं। विनियामक संपत्ति वसूलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने वाला है।

डीईआरसी में चेयरमैन पद खाली होने की स्थिति में उपभोक्ताओं पर असर डालने वाले नोटिफिकेशन पर भी प्रश्न उठाया जा रहा है। डीईआरसी चेयरमैन का पद पिछले लगभग दो माह से रिक्त है। अभी तक दो स्थायी सदस्यों की भी नियुक्ति नहीं हुई है। इस समय दो अस्थायी सदस्य के सहारे आयोग चल रहा है। वहीं, पिछले चार वर्षों से आयोग टैरिफ घोषित नहीं कर सका है। नियम अनुसार वित्त वर्ष शुरू होने से पहले बिजली टैरिफ की घोषणा होनी चाहिए। लेकिन, दिल्ली में वर्ष 2021-22 के बाद टैरिफ की घोषणा नहीं हुई है।

पीपीएसी के माध्यम से बिजली महंगी की जा रही है। इसे लेकर विवाद भी होता रहा है। पिछले वर्ष पीपीएसी बढ़ने पर भाजपा ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी डिस्कॉम को पीपीएसी वसूलने की अनुमति दी जा रही है।

ईंधन की लागत बढ़ने पर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। बिजली खरीद व उपभोक्ताओं को निर्धारित दर बिजली आपूर्ति में होने वाले घाटे की भरपाई के लिए डिस्काम पीपीएसी वसूलती है। डिस्कॉम के आवेदन पर डीईआरसी एक तिमाही के लिए पीपीएसी का निर्धारण करता है। अब डिस्कॉम को प्रत्येक माह 10 प्रतिशत तक अपने स्तर पर पीपीएसी निर्धारित कर उपभोक्ताओं से वसूलने का अधिकार मिल जाएगा। इसमें ट्रांसमिशन शुल्क भी शामिल किया गया है। डीईआरसी के इस प्रस्ताव पर उपभोक्ता व अन्य हित धारक 24 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसके पहले ही विरोध शुरू हो गया है।

डिस्कॉम के खातों की जांच कराने की मांग

आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों कहना है कि पिछले कई वर्षों से डिस्कॉम के खातों की जांच कराने की मांग की जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार और डीईआरसी की लापरवाही से डिस्कॉम को सुप्रीम कोर्ट से विनियामक संपत्ति वसूलने की अनुमति मिल गई है।

उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है 27000 करोड़ का बोझ

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में तीनों निजी बिजली वितरण कंपनियां बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस राजधानी यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) को कुल 27200.37 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का भुगतान अधिकतम चार वर्ष में सभी बकाया का भुगतान हो जाना चाहिए।

इससे दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है, क्योंकि विनियामक संपत्ति उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। इस समय उपभोक्ताओं से बिजली बिल पर आठ प्रतिशत नियामक अधिभार वसूला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने पर इसमें और वृद्धि होगी। उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर स्थायी शुल्क, पेंशन अधिभार भी देना पड़ता है।

दिल्ली में बिजली उपभोक्ता

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली) - 30.5 लाख

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (पूर्वी व मध्य दिल्ली) - 20 लाख

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (उत्तरी दिल्ली) - 19 लाख

पत्र — संवाद नहीं, भावनाओं का सजीव दस्तावेज़

पत्र, वह कालजयी कला है, जो शब्दों के जादू से हृदय को हृदय से जोड़ती है। जब डिजिटल संदेशों की सतही चमक में दुनिया खोई हुई है, तब कागज़ पर स्याही से लिखे शब्द ही वह जादू बुनते हैं, जो समय और दूरी को लांघकर आत्मा को छू लेता है। विश्व पत्र लेखन दिवस महज एक तारीख नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य का उत्सव है, जो हमें याद दिलाता है कि मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे गहरा और प्रामाणिक माध्यम पत्र ही है। यह वह सेतु है, जो विचारों को नहीं, बल्कि भावनाओं को अमर बनाता है। स्याही की एक बूंद में छिपी वह गर्माहट, जो किसी के मन को सहलाए, यही पत्र का सच्चा सार है।

पत्र लेखन की जड़ें मानव सभ्यता की गहराइयों में बसी हैं। प्राचीन काल में, जब संचार के साधन दुर्लभ थे, कबूतरों की उड़ान और दूतों की यात्राएँ संदेशों को एक कोने से दूसरे तक ले जाती थीं। भारतीय इतिहास में पत्र लेखन ने संवाद का नहीं, बल्कि क्रांति और जागृति का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी के पत्र, जो उन्होंने विश्व नेताओं और अनुयायियों को लिखे, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का माध्यम बने। जवाहरलाल नेहरू के अपनी पुत्री को लिखे पत्र इतिहास और संस्कृति का अमूल्य खजाना हैं। भगत सिंह के जेल से लिखे पत्र आज भी युवा हृदयों में स्वतंत्रता की आग जलाते हैं। ये पत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक युग की धड़कनें हैं, जो समय की दीवारों को भेदकर उस दौर की जीवंत तस्वीर उकेरती हैं।

पत्र न केवल व्यक्तिगत भावनाओं का दर्पण है, बल्कि समाज की सशक्त आवाज़ भी है। समाचार पत्रों में "संपादक के नाम पत्र" इसका सबसे जीवंत प्रमाण है। यह वह मंच है, जहाँ आम नागरिक अपनी राय, समस्याओं, सुझावों और आलोचनाओं को समाज और शासन तक निर्भीक होकर पहुँचाता है। यह स्तंभ हर व्यक्ति को अपनी बात तर्कपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से रखने की ताकत देता है। एक बार महिदपुर उज्जैन के पत्र लेखक जवाहर डोसीजी का एक पत्र स्थानीय समाचार पत्र में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने अंगदान करने वालों के लिए सम्मान की माँग सरकार से की थी। उनकी स्पष्टता और तार्किकता इतनी प्रबल थी कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में आदेश जारी कर दिए। यह अनुभव मेरे लिए एक प्रेरणा बना, जिसने सिखाया कि एक पत्र न केवल निजी संवाद का सेतु है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली हथियार भी हो सकता है।

आधुनिक युग में, जब संदेश पलक झपकते विश्व के एक छोर से दूसरे तक पहुँच जाते हैं, पत्र लेखन की प्रासंगिकता और भी गहरी हो जाती है। डिजिटल संदेशों की आपाधापी में वह आत्मीयता कहाँ, जो कागज़ पर उकेरे गए शब्दों में बसती है? पत्र लेखन केवल शब्दों को पिरोना नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से भावनाओं को तराशना है। यह एक ऐसी कला है, जो लेखक और पाठक के बीच एक अनदेखा, अटूट बंधन रचती है। जब हम कलम उठाते हैं, तो वह स्याही नहीं, बल्कि हमारे विचारों, सपनों और संवेदनाओं का अमर प्रवाह होता है। यह वह पल है, जब हम अपने मन की गहराइयों में गोता लगाते हैं और शब्दों को वह शक्ति देते हैं, जो समय की हर सीमा को लांघ जाती है।

पत्र लेखन ने इतिहास के पन्नों पर कई बार समाज को नई राह दिखाई है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के पत्र महज निजी संदेश नहीं थे; वे जन-जागरण और प्रेरणा के स्रोत बनकर उभरे। सुभाष चंद्र बोस के पत्रों में उनकी संगठन शक्ति और देशभक्ति की प्रचंड ज्वाला साकार हो उठती थी। रवींद्रनाथ टैगोर के पत्र साहित्य और दर्शन का अमूल्य खजाना हैं। ये पत्र केवल संदेश नहीं, बल्कि एक युग की चेतना को अमर करने वाले जीवंत दस्तावेज़ हैं। जब मैं इन पत्रों को पढ़ता हूँ, तो अनुभव करता हूँ कि शब्दों में वह शक्ति है, जो न केवल व्यक्तियों, बल्कि समाज और इतिहास की दिशा को भी बदल सकती है।

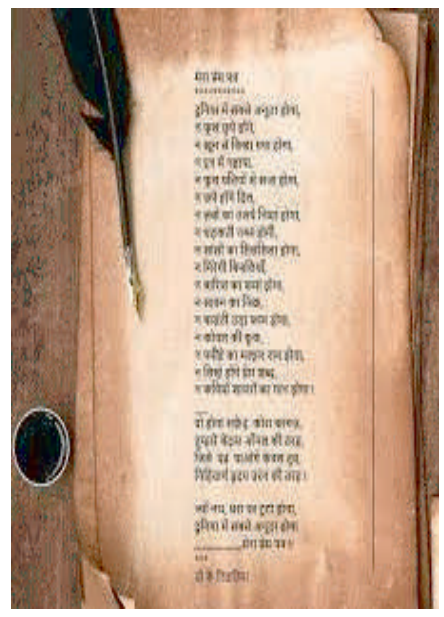

विश्व पत्र लेखन दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस अमर कला को कैसे जीवित रखें। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मानवता की वह विरासत है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। आज की पीढ़ी, जो त्वरित संदेशों और डिजिटल संवाद की आदी हो चुकी है, उसे यह समझने की ज़रूरत है कि सच्चा संवाद वही है जो आत्मा को छू जाए। एक हस्तलिखित पत्र में वह धैर्य और समर्पण होता है जो डिजिटल संदेशों में नहीं मिलता। यह वह माध्यम है जो हमें अपने विचारों को गहराई से व्यक्त करने और दूसरों के साथ एक गहरा बंधन बनाने का अवसर देता है।

पत्र लेखन का एक और अनमोल पहलू यह है कि यह यादों को अमर बनाता है। पीले पड़ चुके कागज़ों पर लिखे पुराने पत्र समय को थाम लेते हैं, हमें उस पल में ले जाते हैं जब स्याही ने कागज़ को छुआ था। उन शब्दों में बसी भावनाएँ—चाहे प्रेम की उष्मा, दुख की गहराई, या आशा की किरण—हमें अपनों की सजीव उपस्थिति का एहसास कराती हैं। यही वह जादू है जो पत्र लेखन को अनुपम बनाता है। यह हमें सिखाता है कि संवाद केवल सूचनाओं का लेन-देन नहीं, बल्कि भावनाओं का एक पवित्र संगम है, जो समय की सीमाओं को लांघ जाता है।

विश्व पत्र लेखन दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम इस अनमोल कला को पुनः अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएँ। यह वह अवसर है जब हम भागदौड़ भरी दुनिया में एक पल ठहरकर अपने हृदय की गहराइयों में उतरें और अपनों को वह अनुपम उपहार दें, जो केवल शब्दों की स्याही से रचा जा सकता है। यह दिन हमें आत्ममंथन का न्योता देता है—कब आखिरी बार हमने अपने दिल की गूँज को कागज़ पर उकेरा था? यदि जवाब धुंधला हो, तो यही वह क्षण है जब हमें कलम उठाकर अपने शब्दों को वह जादुई शक्ति प्रदान करनी चाहिए, जो किसी के जीवन को प्रेम और प्रेरणा से आलोकित कर दे।

पत्र लेखन न केवल अतीत की अनमोल विरासत है, बल्कि भविष्य की अपरिहार्य जरूरत भी। यह हमें सिखाता है कि संवाद का असली मकसद सिर्फ जानकारी का लेन-देन नहीं, बल्कि भावनाओं का गहरा संयोजन है। यह वह कला है जो हमें खुद से और अपनों से जोड़ती है, वह आईना है जिसमें हम अपनी आत्मा की छवि देखते हैं। विश्व पत्र लेखन दिवस हमें याद दिलाता है कि शब्द महज ध्वनियाँ नहीं, बल्कि वे अमर सूत्र हैं जो मानवता को एकजुट करते हैं। इस दिन प्रण करें कि हम इस कला को न केवल जीवंत रखेंगे, बल्कि इसे पनपने देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उस आत्मीयता और स्नेह को महसूस करें, जो सिर्फ एक पत्र की स्याही में समाई हो सकती है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

संविधान की शक्ति के आगे ट्रंप लाचार

डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने वैश्विक व्यापार को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखा, को 29 अगस्त को अमेरिकी फेडरल सर्किट अपीलीय अदालत ने करारा झटका दिया। 7-4 के ऐतिहासिक फैसले में ट्रंप के 'रेसिप्रोकल' टैरिफ को गैरकानूनी और अमान्य करार दिया गया। यह टैरिफ चीन, मैक्सिको, कनाडा और अन्य देशों पर थोपे गए, ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का आधार थे। अदालत ने दो टूक कहा, राष्ट्रपति की शक्ति संविधान से ऊपर नहीं। इस फैसले ने न केवल ट्रंप की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की हवा निकाल दी, बल्कि वैश्विक व्यापार में नए तनाव की आहट दी। 14 अक्टूबर तक यह फैसला लागू नहीं होगा, जिससे ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका मिला है। यह कानूनी जंग अब वैश्विक अर्थव्यवस्था, अमेरिकी लोकतंत्र और ट्रंप की विदेश नीति के भविष्य को दांव पर लगा रहा है।

फरवरी 2025 में, अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर कड़े टैरिफ थोपकर फेंटेनिल तस्करी और अवैध आप्रवासन पर प्रहार किया। अप्रैल 2025 में, उन्होंने नाटकीय 'लिबरेशन डे' घोषणा में दुनिया भर पर 10% बेसलाइन टैरिफ लाद दिया, जिसमें चीन पर 34% और भारत पर 50% जैसे सख्त 'रेसिप्रोकल' टैरिफ शामिल थे। ट्रंप का तर्क था कि 2024 का $1.2 ट्रिलियन का व्यापार घाटा (यूएस सेंसस ब्यूरो) अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खोखला कर रहा है, जिससे विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखलाएँ और सैन्य शक्ति कमजोर हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) का सहारा लिया, व्यापार घाटे और फेंटेनिल संकट को 'राष्ट्रीय आपातकाल' करार दिया। मगर अदालत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, ट्रंप की इस महत्वाकांक्षी नीति पर गहरे सवाल खड़े कर दिए।

फेडरल सर्किट अपीलीय अदालत ने 7-4 के ऐतिहासिक फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ तर्क को ध्वस्त कर दिया। अदालत ने साफ कहा, 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। अदालत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया, "आईईईपीए कर लगाने का अधिकार नहीं देता।" यह कानून प्रतिबंधों, जैसे विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करने, के लिए है, न कि टैरिफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 'मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन' का हवाला देते हुए अदालत ने माना कि बड़े आर्थिक प्रभाव वाले फैसलों के लिए कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी जरूरी है। ट्रंप का आईईईपीए का इस्तेमाल 'अनपेक्षित' और संवैधानिक शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ था।

अदालत ने दो आधारों पर टैरिफ को खारिज किया। पहला, व्यापार घाटा कोई 'राष्ट्रीय आपातकाल' नहीं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक, 1970 के दशक से अमेरिका व्यापार घाटे में है—यह कोई नया खतरा नहीं। दूसरा, फेंटेनिल से जुड़े टैरिफ समस्या का समाधान नहीं, बल्कि दबाव का हथियार हैं। संविधान के अनुच्छेद 1, धारा 8 के तहत, कर लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस का है। आईईईपीए के जरिए ट्रंप का यह कदम संविधान को चुनौती था। यह फैसला मई 2025 के यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के निर्णय को और मजबूत देता है, जिसमें ट्रंप द्वारा नियुक्त जज भी शामिल थे।

कनाडा पर लगे 'ट्रैफिकिंग टैरिफ' अब गैरकानूनी ठहराए गए हैं। यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ टैरिफ पर आधारित व्यापार समझौते अब डगमगा रहे हैं। ट्रंप का दावा था कि ये टैरिफ अमेरिकी विनिर्माण को फिर से जागृत करेंगे, लेकिन टैक्स फाउंडेशन का अनुमान उल्टा है: 2025 में प्रत्येक अमेरिकी परिवार पर $1,300 का अतिरिक्त बोझ, 1.2% बढ़ती मुद्रास्फीति और जीडीपी में 0.9% की गिरावट। एनपीआर की चेतावनी है कि ये टैरिफ 1930 के स्मूट-हॉले टैरिफ एक्ट के बाद सबसे भारी हैं, जिसने ग्रेट डिप्रेशन को और गहरा किया था।

बाजारों में उथल-पुथल मची है। फैसले के बाद स्टॉक मार्केट में हल्की उछाल देखी गई, लेकिन अनिश्चितता का साया बरकरार है। आयात पर निर्भर छोटे व्यवसाय सबसे ज्यादा चपेट में आएंगे। भारत जैसे देशों पर 50% टैरिफ ने उनके निर्यात को पहले ही झटका दिया था। अब यह फैसला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को कुछ राहत दे सकता है, लेकिन ट्रंप की आर्थिक रणनीति पर सवालों का बादल मंडरा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के फैसले को 'पक्षपातपूर्ण' ठहराते हुए आग उगली। उन्होंने कहा- "ये जज अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं। टैरिफ के बिना हमारा विनिर्माण खत्म हो जाएगा।" व्हाइट हाउस ने इसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हथियार बताकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में 6-3 का कंजर्वेटिव बहुमत है, जिसमें ट्रंप द्वारा नियुक्त तीन जज शामिल हैं। मगर 'मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन' और 'नॉन-डेलिगेशन डॉक्ट्रिन' उनके रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। हाल ही में ईपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बड़े निर्णयों के लिए कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में गया, तो राष्ट्रपति को अभूतपूर्व आर्थिक शक्ति मिल सकती है। अगर नहीं, तो कांग्रेस को टैरिफ नीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।

ट्रंप के पास वैकल्पिक रास्ते हैं। सेक्शन 232 (ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, 1962) स्टील और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों में टैरिफ की इजाजत देता है, लेकिन इसमें लंबी जांच और सुनवाई की जरूरत है। सेक्शन 301 (ट्रेड एक्ट, 1974) अनुचित व्यापार प्रथाओं, जैसे चीन की, के खिलाफ टैरिफ की अनुमति देता है, पर यह आईईईपीए की तुलना में जटिल और धीमा है। ट्रंप की तेज-तर्रार और चौंकाने वाली रणनीति अब गहरे संकट में फंस चुकी है।

अमेरिकी लोकतंत्र की ताकत ने एक बार फिर खुद को साबित किया। फेडरल सर्किट अपीलीय अदालत के फैसले ने स्पष्ट कर दिया- राष्ट्रपति हो या कोई और, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं। लेकिन सवाल बरकरार है, क्या यह ट्रंप की टैरिफ नीति का अंत है, या सुप्रीम कोर्ट में नई जंग की शुरुआत? 2026 तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैश्विक व्यापार और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अनिश्चितता के बादल में छाए रखेगा। ट्रंप ने टैरिफ के बल पर अमेरिका को फिर से महान बनाने का सपना देखा था, मगर अदालत ने सिद्ध किया कि असली शक्ति संविधान और कानून की सर्वोच्चता में निहित है। यह एक ऐसा युद्ध है, जहाँ कानून की किताबें तलवारों से तेज हैं, और जीत उसी की होगी जो संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करे।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत",

शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी : सुविधा से जंजाल तक की यात्रा

हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, जो 2016 में शिक्षकों के लिए पारदर्शिता का प्रतीक बनकर आई थी, अब उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। वर्षों से ट्रांसफर लंबित हैं, ब्लॉक सिस्टम बाधा बन गया है और विद्यालयों में शिक्षकों का असंतुलन गहरा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव चलाए और पॉलिसी में सुधार करे, ताकि न तो शिक्षक परेशान हों और न ही छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो।

डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी। उस समय इसे शिक्षा जगत में बड़े सुधार के रूप में देखा गया। दशकों से यह आरोप लगता रहा कि तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी रहते थे। कई शिक्षक मनचाही जगह सेवा करते थे जबकि अन्य दूरदराज़ और कठिन क्षेत्रों में वर्षों तक फंसे रहते थे। इस असमानता ने शिक्षा व्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुँचाया।

ऑनलाइन पॉलिसी ने शुरू में उम्मीद जगाई। कहा गया कि शिक्षक अपनी पसंद और प्राथमिकता ऑनलाइन दर्ज करेंगे और मेरिट के आधार पर तबादला होगा। इससे भेदभाव खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। परंतु नौ साल बाद यह योजना अब विवादों और असंतोष का दूसरा नाम बन चुकी है।

आश्वासन और हकीकत

हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले आश्वासन दिया जाता है कि ट्रांसफर होंगे, लेकिन अक्सर यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इस साल भी अप्रैल में घोषणा की गई थी कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ट्रांसफर सत्र शुरू होने से पहले कर दिए जाएंगे। मगर अगस्त बीत गया और शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। जब-जब ऐसी घोषणाएँ अधूरी रह जाती हैं, तो शिक्षकों का मनोबल टूटता है और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

ब्लॉक सिस्टम की पेचीदगी

इस नीति की सबसे बड़ी खामी "ब्लॉक सिस्टम" है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक सुविधा मिलती है और शिक्षक नज़दीकी ब्लॉक में ही स्थानांतरित होते हैं। लेकिन व्यवहार में यह उल्टा साबित हुआ। कई बार एक ही ब्लॉक में किसी विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी होती है, वहीं कुछ विद्यालयों में जरूरत से ज्यादा स्टाफ मौजूद होता है। नीति की जटिलता के कारण समायोजन नहीं हो पाता और विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

एक उदाहरण समझिए—मान लीजिए एक ब्लॉक में गणित के शिक्षक की 15 सीटें हैं लेकिन वहां 20 शिक्षक तैनात हैं, जबकि उसी जिले के दूसरे ब्लॉक में 10 सीटें खाली पड़ी हैं। ब्लॉक सिस्टम के कारण अतिरिक्त शिक्षक चाहकर भी खाली स्कूलों में नहीं भेजे जा सकते। इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है।

शिक्षकों का दृष्टिकोण

शिक्षक केवल अपनी सुविधा के लिए तबादले नहीं मांगते। वे चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चले, ताकि उनकी मेहनत सार्थक हो सके। जब वर्षों तक ट्रांसफर लंबित रहते हैं, तो शिक्षक घर-परिवार से दूर रहकर मानसिक तनाव झेलते हैं। कई महिला शिक्षक छोटे बच्चों को छोड़कर दूरदराज़ स्थानों पर सेवाएँ दे रही हैं। ऐसे हालात में उनका मन पढ़ाई पर कितना केंद्रित रह पाता होगा, यह सोचना मुश्किल नहीं।

दूसरी ओर, कई शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह टिके हुए हैं। इससे उन पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। यह भी सच है कि लंबे समय तक एक ही विद्यालय में रहने वाले शिक्षक और प्रधानाध्यापक स्थानीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं और शिक्षा से ज्यादा निजी हितों में उलझ जाते हैं। इस असंतुलन को खत्म करना बेहद ज़रूरी है।

शिक्षा पर असर

जब किसी विद्यालय में वर्षों तक विज्ञान या गणित का शिक्षक नहीं होता, तो छात्र पीछे रह जाते हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम गिरते हैं और इसका दोष अक्सर छात्रों या अभिभावकों पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन असली जिम्मेदार प्रणाली है, जो समय पर सही अध्यापक नहीं भेज पाती। शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) कहता है कि हर विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी की कमजोरियों ने इस लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया है।

संगठन की भूमिका

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार को समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव शुरू करनी चाहिए। यदि कोई स्कूल खाली रह जाता है, तो जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को डिप्यूटेशन का अधिकार दिया जाए। यह सुझाव व्यवहारिक है, क्योंकि इससे तत्कालीन संकट टाला जा सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी इच्छाशक्ति दिखाएगी? कई बार लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी का उपयोग प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। जब चाहा प्रक्रिया रोक दी जाती है और जब चाहा कुछ तबादले चुनिंदा लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। इससे शिक्षकों का विश्वास डगमगाता है।

डिजिटलाइजेशन बनाम ज़मीनी हकीकत

सरकार ने पॉलिसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालकर इसे "ई-गवर्नेंस" की सफलता बताया। लेकिन केवल पोर्टल बना देने से समस्या हल नहीं होती। डिजिटल प्लेटफॉर्म तभी सफल होता है जब उसमें समयबद्धता और जवाबदेही हो। यदि हर साल प्रक्रिया अधूरी ही छोड़ दी जाए, तो ऑनलाइन सिस्टम भी महज़ दिखावा बनकर रह जाता है।

आज हाल यह है कि कई शिक्षक हर साल ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फीस जमा करते हैं, दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, लेकिन अंत में परिणाम "कोई ट्रांसफर नहीं" निकलता है। ऐसे में उनमें गुस्सा और हताशा स्वाभाविक है।

शिक्षा मंत्री और हकीकत

शिक्षा मंत्री बार-बार कहते हैं कि "जल्द ही ट्रांसफर होंगे" लेकिन नौकरशाही और नीति की जटिलता के कारण बात आगे नहीं बढ़ती। इस बीच, सत्र बीत जाता है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा में रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती।

समाधान क्या है?

1. ब्लॉक सिस्टम की समीक्षा – इसे या तो खत्म किया जाए या लचीला बनाया जाए, ताकि शिक्षक जरूरत वाले स्कूलों तक पहुँच सकें।
2. समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव – हर साल अप्रैल से पहले प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य किया जाए।
3. डिप्यूटेशन का अधिकार जिला स्तर पर – खाली स्कूलों को भरने के लिए अधिकारियों को अधिकार दिया जाए।
4. पारदर्शिता और जवाबदेही – यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होता, तो स्पष्ट कारण बताए जाएं।
5. मानवीय दृष्टिकोण – महिला शिक्षकों, विकलांग शिक्षकों और कठिन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान हों।

शिक्षा की आत्मा

समाज में शिक्षा सबसे पवित्र कार्य है। यदि शिक्षक ही असंतोष में रहेंगे, तो वे विद्यार्थियों तक सकारात्मक ऊर्जा कैसे पहुँचाएंगे? एक निराश और हताश शिक्षक बच्चों को वही भाव देगा जो उसके भीतर है। इसलिए शिक्षक की समस्याओं को केवल "ट्रांसफर की मांग" मानकर टालना सही नहीं। यह शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को मज़बूत करने का सवाल है।

सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों को केवल "डाटा" न माने, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला समझे। शिक्षक का मनोबल तभी ऊँचा होगा जब उसे न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी।

सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डा

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा करके उसमें आवश्यक सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक इस नीति में पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय दृष्टिकोण नहीं जुड़ता, तब तक यह केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती फाइलें भर रहेगी, जमीनी हकीकत में नहीं।

शिक्षकों की आवाज़ अनसुनी करना न सिर्फ उनके साथ अन्याय है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। सरकार को तुरंत कदम उठाकर इस जंजाल को दूर करना चाहिए। तभी शिक्षा का स्तर सुधरेगा और शिक्षक अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा पाएंगे।

अभद्र और अराजक भाषा से लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा, देश की छवि पर भी गहराया संकट : समाजसेवीयों की चेतावनी

"आलोचना कीजिए, जितनी चाहें कीजिए, लेकिन भाषा का स्तर न गिराइए"

"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ कदापि नहीं कि किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाई जाए या समाज में विष घोला जाए"

उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे विचारधारा आधारित राजनीति को बढ़ावा दें और अपने कार्यकर्ताओं को संयम व मर्यादा का पाठ पढ़ाएं

आगरा, संजय साग़र सिंह। देश में राजनीतिक विमर्श के गिरते स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने कहा है कि लोकतंत्र में आलोचना आवश्यक है, किंतु उसकी भाषा मर्यादित और शालीन होनी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि अभद्र, अशोभनीय और अराजक भाषा का प्रयोग केवल बहस को दिशाहीन और समाज को विघटित करता है, साथ ही यह देश की छवि को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का कार्य करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में विरोध, असहमति और आलोचना किसी भी शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, परंतु जब यह आलोचना शालीनता की सीमाएं लांघने लगती है, तब यह न सिर्फ अमर्यादित होती है, बल्कि पूरे लोकतंत्र को भी कमजोर करती है।

आलोचना कीजिए, जितनी चाहें कीजिए, लेकिन भाषा का स्तर न गिराइए - वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान साहब

राजनीति में गिरते स्तर पर गहरी चिंता वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान साहब ने देश में खासकर चुनावों के दौरान राजनीति में आए तीखेपन और कटुता पर गंभीर चिंता प्रकट की। उन्होंने हाल ही में हुई राजनीतिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि नेताओं द्वारा उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के प्रति की जा रही अमर्यादित टिप्पणियाँ न केवल व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि इससे संपूर्ण राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर भी आघात होता है। राजनीति विचारों की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, न कि कटुता, अपशब्द और निजी हमलों का अखाड़ा। चुनावों के समय यह प्रक्रिया और विषैली हो जाती है, जो अत्यंत दुखद है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे विचारधारा आधारित राजनीति को बढ़ावा दें और अपने कार्यकर्ताओं को संयम व मर्यादा का पाठ पढ़ाएं। आलोचना कीजिए, जितनी चाहें कीजिए, लेकिन भाषा का स्तर न गिराइए।

संविधान नहीं देता अभद्रता की इजाजत - समाजसेवी अरविन्द पुष्कर एडवोकेट

समाजसेवी अरविन्द पुष्कर एडवोकेट ने जोर देते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, परंतु यह स्वतंत्रता अनुशासन और सामाजिक मर्यादा से बंधी हुई है। अभद्र भाषा और अशोभनीय व्यवहार न केवल समाज में विष घोलते हैं, बल्कि यह संवैधानिक मर्यादाओं का भी घोर उल्लंघन है। उन्होंने दो टूक कहा ₹अगर कोई और मर्यादा तोड़ता है, तो हमें उसकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे सिवाय बदनामी और फजीहत के कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि देश को सही दिशा में ले जाना है, तो संवाद की भाषा को सभ्य बनाना ही होगा। राजनीति में पदों पर बैठे लोगों की आलोचना जरूर हो, पर वह आलोचना गरिमा, तर्क और तथ्य आधारित होनी चाहिए।

असहमति के बावजूद संवाद और बहस को मर्यादित बनाए रखना ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान - समाजसेवी पंकज जैन

समाजसेवी पंकज जैन ने कहा कि "आलोचना कीजिए, जितनी चाहें कीजिए, लेकिन भाषा का स्तर न गिराइए₹ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ कदापि नहीं कि किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाई जाए या समाज में विष घोला जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे आलोचना करते समय संतुलित और संयमित शब्दों का प्रयोग करें। अभद्र और अराजक भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अत्यंत चिंतनीय है। देश की छवि पर भी संकट गहराता हैं। अमर्यादित और अराजक भाषा न केवल व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि इससे पुरे देश की प्रतिष्ठा पर भी आघात होता है।

युवाओं को अस्तित्व समझना होगा...!

छात्र व युवा असफलता के बाद आत्महत्या,
एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या।
ये केवल व्यक्तिगत विफलता के संकेत नहीं,
समझ ही नहीं आता कौन गलत कौन सही!
ये बच्चे इतना कठोर कदम क्यों?उठा रहे हैं,
पीड़ति पालकों के कलेजे भी बैठे जा रहे हैं।

स्कूल-कॉलेजों सिर्फ अंक-सफलता की रट,
शिक्षा प्रणाली की बहुत गहरी होती है रपट।
जीवन के महत्वपूर्ण पाठ ना पढ़ जाता खट,
असफलता को स्वीकारना नहीं पाता हैं पढ़।

भावनाओं को संभालना, मानसिक मजबूती,
कहीं भी पढ़ाए न जाते ना होती ये अनुभूति।

युवाओं तुम्हें अपना अस्तित्व समझना होगा,
विफलताओं को भी स्वयं ग्रहण करना होगा।
माता-पिता व समाज का दबाव सहना होगा,
इस मानसिक संकट को भी दूर करना होगा।
लगातार तुलना, ताने और लोग क्या? कहेंगे,
ये ठान लो जीवन में डटकर मुकाबला करेंगे।
(संदर्भ-युवा असफलता में करते आत्महत्या?)

संजय एम तराणेकर

एससीओ शिखर सम्मेलन, वैश्विक शक्ति संतुलन और ट्रंप के खिलाफ़ नया पावर शो-एक मंच पर मोदी-पुतिन और जिनपिंग- दिखेगा शक्ति प्रदर्शन

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया

वैश्विक स्तरपर एससीओ शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में हो रहा है, बदलते वैश्विक परिपेक्ष में इसपर पूरे विश्व की नजरें लगी हुई है।उधरभारत के पीएम ने जापान यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और भारत-जापान संबंधों को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया।जापान में तकनीकी, व्यापारिक, रक्षा और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल करनेके तुरंत बाद पीएम सीधे चीन के तियानजिन पहुँचे, जहाँ 31 अगस्त 2025 से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का वार्षिक शिखर सम्मेलन आरंभ हो रहा है। यह महज एक राजनयिक यात्रा नहीं बल्कि एशिया और विश्व राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में मोदी,शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे और यह उपस्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और उनके ₹अमेरिका फर्स्ट₹ एजेंडे के खिलाफ एक सामूहिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, एससीओ शिखर सम्मेलन वैश्विक शक्ति संतुलन और ट्रंप के खिलाफ़ नया पावर शो-एक मंच पर मोदी-पुतिन और जिनपिंग- दिखेगा शक्ति प्रदर्शन।

साथियों बात अगर हम जापान में मोदी की कूटनीतिक जीत की करें तो,उनकी जापान यात्रा और उसके तुरंतबाद चीन के तियानजिन में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ने एशिया और विश्व राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जापान में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बाद मोदी जब चीन पहुँचे तो यह केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा बदलने वाला कदमसाबित हुआ।उनकी जापान यात्रा इस लिहाज से ऐतिहासिक रही कि भारत और जापान ने बुलेट ट्रेन,रक्षा साझेदारी, सेमीकंडक्टर निर्माण, अक्षय ऊर्जा और डिजिटल सहयोग जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्तर के समझौतों पर सहमति जताई। जापान ने भारत को न केवल वित्तीय सहयोग बल्कि तकनीकी हस्तांतरण में भी बड़ा कदम उठाया। इन समझौतों ने एशिया में भारत की स्थिति को और मजबूत किया है।जापान पहले से ही भारत का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन इस बार हुए समझौतों ने दोनों देशों को ₹भविष्य के सह-निर्माता₹ के रूप मेंस्थापित कर दिया है। इस सफलता के झंडे गाड़ने के बाद मोदी का चीन पहुँचना इस बात का प्रतीक है कि भारत अब केवल द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि बहुपक्षीय वैश्विक गठबंधनों में निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है।

साथियों बात अगर हम चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन की अहमियत की करें तो,चीन के तियानजिन में होनेवाला यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनियाँ अमेरिका की व्यापारिक नीतियों से असहज है। ट्रंप ने हाल ही में भारत, चीन, रूस और अन्य कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके जवाब में एससीओ देशों का यह मंच एकजुटता का संदेश देने जा रहा है। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मौजूदगी अपने आप में यह संकेत है कि एशिया और यूरेशिया के देश अमेरिका की नीतियों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। भारत का इस मंच पर सक्रिय होना भी दर्शाता है कि वह केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है।

साथियों बात अगर हम एससीओ सम्मेलन ट्रंप केखिलाफ एक पावर शो साबित होने की करें तो, शिखर सम्मेलन में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की एकजुटता को पश्चिमी मीडिया ने पहले से ही ₹एंटी-ट्रंप पावर शो₹ करार दिया है। इन तीनों नेताओं की उपस्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति को यह कड़ा संदेश देती है कि उनकी एकतरफा नीतियाँ अब विश्व को स्वीकार्य नहीं हैं। यह मंच दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और सबसे सशक्त सैन्य ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये शक्तियाँ एकजुट होकर ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ खड़ी होती हैं, तो यह संदेश साफ़ है कि वैश्विक व्यापार और राजनीति केवल वॉशिंगटन की शर्तों पर नहीं चलेगातियानजिन सम्मेलन में जिनपिंग की अगुवाई में होने वाली ₹विक्ट्री परेड₹ में 26 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इसे महज़ एक परेड नहीं बल्कि दुनिया की नई शक्ति-व्यवस्था का प्रदर्शन कहा जा रहा है। रेड कारपेट पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मौजूदगी यह संकेत देती है कि अमेरिका और यूरोप के पारंपरिक प्रभुत्व के दिन अब चुनौती के घेरे में हैं। चीन इस सम्मेलन को अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में दिखाना चाहता है, वहीं भारत इस मंच के ज़रिए संतुलित लेकिन मज़बूत भूमिका निभाने जा रहा है।

साथियों बात कर हम इस सम्मेलन के थ्रू अमेरिका को कड़ा संदेश देने की करें तो,एससीओ शिखर सम्मेलन से निकलने वाला सबसे बड़ा संदेश अमेरिका के लिए होगा। यह संदेश साफ़ है कि ₹हम आपके टैरिफ से डरने वाले नहीं हैं।₹ एससीओ के सदस्य देश और उनके साझेदार यह जताना चाहते हैं कि वे मिलकर न केवल अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करेंगे बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई राह बनाएंगे। अमेरिका के 50 पर्सेंट टैरिफ के बावजूद भारत, चीन और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएँ मजबूती से साथ खड़ी हैं। यह संकेत है कि ट्रंप की नीतियाँ अब विश्व राजनीति को बाँटने में असफल हो रही हैं और इसके बजाय देश आपसी सहयोग के नए रास्ते खोज रहे हैं।

साथियों बात अगर हम विक्ट्री परेड और नई वैश्विक तस्वीर के रूप में देखने की करेंतो,जिनपिंग की अगुवाई में होने वाली विक्ट्री परेड केवल चीन की शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि सामूहिक एकता का प्रतीक है।इसमें शामिल 26 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि दुनियाँ अमेरिका की एकतरफा नीतियों से निकलकर सामूहिक नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। भारत का इसमें शामिल होना विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत ने हमेशा संतुलित कूटनीति अपनाई है। अब वह खुलकर वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन रहा है। यह परेड आने वाले वर्षों में विश्व राजनीति का नया नक्शा खींचने वाली साबित हो सकती है।

साथियों बात अगर हम अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बनने की करें तो,दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से सिर्फ बाहर की दुनिया ही परेशान नहीं है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी उनके खिलाफ माहौल बन चुका है। अमेरिकी किसान, टेक कंपनियाँ और उपभोक्ता समूह लगातार विरोध जता रहे हैं कि टैरिफ ने उनकी लागत बढ़ा दी है और प्रतिस्पर्धा कमजोर कर दी है। ऐसे में जब बाहर की दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो और अमेरिका के भीतर भी उनकी नीतियों पर सवाल उठ रहे हों, तो यह माना जा रहा है कि तियानजिन सम्मेलन वैश्विक राजनीति में ₹टर्निंग प्वाइंट₹ साबित हो सकता है।

साथियों बात अगर कर हम वैश्विक गठबंधनों की नई तस्वीर,अमेरिका को कड़ा संदेश:₹हम डरने वाले नहीं₹ की करें तो,एससीओ सम्मेलन से जो सबसे बड़ी आवाज़ निकलेगी, वह होगी- ₹टैरिफ हमें रोक नहीं सकते।₹यह संदेश सीधे अमेरिका को है। भारत, चीन, रूस और अन्य देश यह बताना चाहते हैं कि वे विकल्प तैयार कर सकते हैं। नई मुद्रा व्यवस्था, वैकल्पिक व्यापार नेटवर्क,डिजिटलभुगतान तंत्र और क्षेत्रीय आपसी समझौते, ये सब अमेरिकी डॉलर और टैरिफ के प्रभाव कोकमजोर करेंगे। भारत की ₹प्लान 40₹ नीति (40 देशों के नए बाजार खोजने की रणनीति) पहले ही संकेत दे चुकी है कि टैरिफ के बावजूद भारत पीछे हटने वाला नहीं है।इस सम्मेलन से यह साफ हो गया है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक गठबंधन नई दिशा लेंगे। नाटो और यूरोपीय संघ का प्रभाव पहले ही सीमित हो रहा है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंच अब विकल्प बन रहे हैं। भारत-जापान साझेदारी, रूस- चीन करीबी और एशिया-मध्य एशिया का एकीकरण-यह सब मिलकर वैश्विक राजनीति का नया नक्शा खींच रहे हैं। यह स्थिति अमेरिका के लिए कठिन है क्योंकि उसकी पारंपरिक रणनीति ₹डिवाइड एंड रूल₹ अब काम नहीं आ रही।

साथयों बात अगर हम भविष्य का परिदृश्य की कपिल कल्पना करने की करें तो,एससीओ सम्मेलन और मोदी- जिनपिंग- पुतिन की तिकड़ी केवल ट्रंप विरोध तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह नई आर्थिक और सामरिक व्यवस्था की नींव रख सकती है। बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ते कदम से अमेरिका का एकछत्र वर्चस्व चुनौती के घेरे में आएगा। भारत के लिए यह अवसर है कि वह अपनी ₹रणनीतिक स्वायत्तता₹ को बनाए रखते हुए एक बड़ेशक्ति-गठबंधन का हिस्सा बने। रूस और चीन की साझेदारी के बीच भारत का संतुलनकारी रोल भविष्य में एशिया के शक्ति समीकरण को और मज़बूत बना सकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे किएससीओ शिखर सम्मेलन, वैश्विक शक्ति संतुलन और ट्रंप के खिलाफ़ नया पावर शो-एक मंच पर मोदी-पुतिन और जिनपिंग- दिखेगा शक्ति प्रदर्शनभारत क़ी यह महज एक राजनयिक यात्रा नहीं बल्कि एशिया और विश्व राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है।

एथर एनर्जी ने पेश किया अगली पीढ़ी का ईएल प्लेटफॉर्म और एथरस्टैक 7.0 सॉफ्टवेयर

एथर एनर्जी ने एथर कम्युनिटी डे 2025 में अगली पीढ़ी का ईएल प्लेटफॉर्म एथरस्टैक™ 7.0 सॉफ्टवेयर नेक्स्ट-जेन फास्ट चार्जर्स और इंफिनिट क्रूज कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया। रिज्टा स्कूटर में भी अपडेट्स पेश किए गए। नया ईएल प्लेटफॉर्म वर्सेटिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। एथर ने कॉन्सेप्ट रिडक्स भी दिखाया। एथरस्टैक 7.0 वॉयस इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है। रिज्टा Z को टचस्क्रीन और नया कलर अपडेट मिला है।

नई दिल्ली: भारत की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Ather Energy ने कई बड़े इनोवेशन की घोषणा की है। इसकी घोषणा कंपनी ने Ather Community Day 2025 पर की है। इस इवेंट में कंपनी ने अपनी अगली पीढ़ी का EL प्लेटफॉर्म, नया AtherStack™ 7.0 सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट-जेन फास्ट चार्जर्स और Infinite Cruise क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया। साथ ही, Rizta स्कूटर में भी बड़े अपडेट्स पेश किए गए। ये सभी अपडेट्स Ather के अगले ग्रोथ फेज़ की शुरुआत को दर्शाते हैं और भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में नए मानक स्थापित करने जा रहे हैं। आइए विस्तार में इनके बारे में जानते हैं।

Ather का नया EL प्लेटफॉर्म

Ather ने अपनी पहली जनरेशन के 450 प्लेटफॉर्म के बाद पहली बार नया EL प्लेटफॉर्म पेश किया है। इसे वर्सेटिलिटी, स्केलेबिलिटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म एक ही बेस पर अलग-अलग सेगमेंट के स्कूटर्स बनाने की सुविधा देता है। 26 लाख किलोमीटर के फील्ड डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें नया चेसिस, पावरट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैक तक दिया गया है। साथ ही 15% तेज असेंबली और 2X तेज सर्विसिंग, सर्विस इंटरवल अब 10,000 किमी तक दी जा रही है।

कॉन्सेप्ट Ather Redux दिखाया

Ather ने अपने इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए कई चीजों में बदलाव किया है। इसके तहत बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और कम स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए AEBS दी गई है। इसमें ऑनबोर्ड चार्जर और मोटर कंट्रोलर का इंटीग्रेशन, अब अलग पोर्टेबल चार्जर की ज़रूरत नहीं दी है। परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए Redux दिया गया है। Ather ने एक कॉन्सेप्ट Redux भी दिखाया, जो स्कूटर और मोटरसाइकिल के डायनेमिक्स का अनोखा कॉम्बिनेशन है।

इसमें अल्ट्रा-लाइट एल्युमिनियम फ्रेम, 3D प्रिंटेड सीट, AmplyTex बॉडी पैनल, पोश्चर-आधारित मोड चेंज – स्कूटर से स्पोर्ट बाइक में ट्रांसफॉर्मेशन, राइडिंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इंटरफ़ेस बदलने के लिए Morph-UI और अल्ट्रा-फास्ट एक्सीलरेशन के लिए नया थ्रिलिंग फीचर Take off, वॉयस असिस्टेंट के साथ स्मार्ट राइडिंग दी गई है। Ather ने AtherStack™ 7.0 पेश किया, जो अब वॉयस इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है। इसके जरिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ सहज बातचीत, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ सहज बातचीत, रियल-टाइम अलर्ट्स, लोकेशन शेयरिंग, टायर प्रेशर अपडेट, पोथोल अलर्ट, क्रैश अलर्ट, पार्कसेफ और लॉकसेफ, OTA अपडे, एडवांस्ड क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। इसमें लो-स्पीड से 90 किमी/घंटा तक बिना ब्रेक डिसएंगेज के लिए सिटीक्रूज, चढ़ाई और ढलान पर स्मूद टॉर्क और रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग के लिए हिल कंट्रोल और क्रॉवल कंट्रोल भी दिया गया है।

Rizta Z को मिला अपडेट

Ather Rizta Z को अपडेट दिया गया है। इसमें टचस्क्रीन और नया कलर दिया गया है। इसमें अब टचस्क्रीन डैशबोर्ड, नया टेराकोटा रेड डुअल-टोन कलर और नया Eco Mode मिला है। यह सभी अपडेट्स OTA अपडेट के जरिए मौजूदा ग्राहकों को भी मिलेंगे। Ather ने नया 6 kW फास्ट चार्जर पेश किया है, जो आधे साइज का है और डबल चार्जिंग स्पीड देता है। इसमें 10 मिनट में 30 किमी की रेंज मिलेगी। कुछ चार्जर्स में बिल्ट-इन टायर इंफ्लेटर भी मिलेगा।

सितंबर में लॉन्च होने को तैयार एक से बढ़कर एक कारें, मारुति से लेकर विनफास्ट तक लिस्ट में शामिल

भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। बिक्री बढ़ाने के लिए अधिकतर निर्माता अपनी कारों को अपडेट करते हैं और कुछ नई कारों को पेश और लॉन्च किया जाता है। सितंबर महीने में भी कई कारों को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ऐसी कौन सी कारें हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में वाहन निर्माताओं की ओर से समय समय पर अपनी कारों को अपडेट किया जाता है। इसके साथ ही कई नई कारों को पेश और लॉन्च भी किया जाता है। सितंबर महीने में भी कई कारों को भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। किस निर्माता की ओर से किस गाड़ी को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Escudo होगी लॉन्च

देश की प्रमुख वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सितंबर महीने में नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से तीन सितंबर को Maruti Escudo नाम से नई एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा। यह एसयूवी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाएगी। इसे मारुति की ओर से एरिना डीलरशिप से ऑफर किया जाएगा।

Citroen Basalt X होगी लॉन्च

सिट्रॉएन की ओर से भी भारत में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कूप एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली बेसाल्ट के नए वर्जन एक्स को पांच सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।

Vinfast करेगी दो एसयूवी लॉन्च

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट की ओर से भी छह सितंबर को दो नई एसयूवी को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक निर्माता Vinfast VF6 और VF7 को लॉन्च करेगी। इन दोनों ही एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा।

Mahindra Thar Facelift

महिंद्रा की ओर से ऑफर की जाने वाली तीन दरवाजों वाली थार के फेसलिफ्ट को भी सितंबर महीने में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी इस एसयूवी के लॉन्च की तारीख तय नहीं हुई है। इसके फेसलिफ्ट में थार रॉक्स की तरह डिजाइन और फीचर्स को अपडेट किया जाएगा।

Volvo EX30 होगी लॉन्च

वॉल्वो की ओर से भी कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सितंबर महीने में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Volvo EX30 को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लेनिक अभी इसके लॉन्च की तारीख तय नहीं हुई है।

डुकाटी डेजर्टएक्स रैली पर ₹1.5 लाख तक का डिस्काउंट, 6-राइडिंग मोड्स जैसे एडवांस्ड राइडर एड्स से लैस

डुकाटी इंडिया अपनी DesertX Rally पर 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। यह ऑफर 31 अगस्त 2025 तक के लिए है। DesertX Rally की एक्स-शोरूम कीमत 23.71 लाख रुपये है। इस मोटरसाइकिल में 937cc का डुकाटी टेस्टास्ट्रेटा इंजन है जो 108 bhp की पावर और 92 Nm का टॉर्क देता है। इसमें छह राइडिंग मोड्स भी हैं।

नई दिल्ली। डुकाटी इंडिया अपनी DesertX Rally पर 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इसे खरीदने वालों को 1.5 लाख रुपये का स्टोर क्रेडिट मिलेगा, जिससे वे स्टोर से ही एक्सेसरीज, राइडिंग जैकेट या अन्य सामान खरीद पाएंगे। डुकाटी की इस मोटरसाइकिल यह डिस्काउंट ऑफर केवल 31 अगस्त 2025 तक के लिए दिया जा रहा है।

Ducati DesertX Rally की कीमत

Ducati DesertX Rally की एक्स-शोरूम कीमत 23.71 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि यह डुकाटी डेजर्टएक्स का सबसे महंगा मॉडल है।

डिजाइन और स्टाइलिंग

Ducati DesertX Rally में सामने की तरफ 21-इंच और पीछे 18-इंच का मजबूत व्हील दिया गया है। यह डुकाटी लाइनअप में पहली मोटरसाइकिल है जिसमें ऑफ-रोड के लिए ऐसी खास कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, बाइक को एक नई livery दी गई है। डुकाटी ने इसमें स्टैंडर्ड रूप से पिरिली स्कॉर्पियन रैली एसटीआर टायर दिए गए हैं, राइडर्स सड़क पर बेहतर उपयोग के लिए स्कॉर्पियन ट्रेल II टायर भी चुन सकते हैं।

सस्पेंशन और चेसिस

Ducati DesertX Rally के में बीक-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड और कायबा सस्पेंशन दिया गया है। फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन में एक्स्ट्रा 20 मिमी की यात्रा दी गई है, जिससे ऑफ-रोड हैंडलिंग और आराम बेहतर होता है। नए विकसित सेंट्रल-स्पोक्ड व्हील्स भी पारंपरिक अलॉय रिम्स की तुलना में प्रभाव प्रतिरोध को बेहतर बनाते हैं, जिससे यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर अधिक लचीला बनती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

Ducati DesertX Rally में 937cc का डुकाटी टेस्टास्ट्रेटा 11° ट्विन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 108 bhp की पावर और 92 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन हाईवे पर क्रूजिंग और मुश्किल ऑफ-रोड रास्तों दोनों के लिए आवश्यक पावर और लचीलापन सुनिश्चित करता है।

Ducati DesertX Rally के फीचर्स

इसमें छह राइडिंग मोड्स स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट, एंड्यूरो और रैली दी जाती है। इससे राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। इसमें कॉर्नरिंग एबीएस, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC), और डुकाटी व्हीली कंट्रोल (DWC) जैसे एडवांस्ड राइडर एड्स भी शामिल हैं। डुकाटी मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ 5-इंच का कलर टीएफटी डिस्प्ले स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, म्यूजिक प्लेबैक, कॉल मैनेजमेंट और वैकल्पिक टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स के साथ आती है।

इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन है बेस्ट बाइक?

हीरो ग्लैमर एक्स बनाम होंडा सीबी125 हॉर्नेट
हीरो मोटोकॉर्प ने Hero Glamour X 125 को लॉन्च किया जो क्रूज कंट्रोल वाली सबसे सस्ती बाइक है। इसका मुकाबला Honda CB125 Hornet से है। Glamour X में 124.7cc का इंजन है जबकि Hornet में 123.94 cc का इंजन है। Glamour X में क्रूज कंट्रोल राइडिंग मोड्स और डिजिटल LCD क्लस्टर जैसे फीचर्स हैं जबकि Hornet में TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है।

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में भारत में Hero Glamour X 125 को लॉन्च किया है। भारत में यह सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल वाली बाइक है। इसके साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया गया है। इसका मुकाबला Honda CB125 Hornet से देखने के लिए मिलेगा, जो हाल ही में भारत में लॉन्च हुई है। यह भी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। हम यहां पर इन दोनों (Hero Glamour X Vs Honda CB125 Hornet) बाइक की तुलना करते हुए आपको बता रहे हैं कि इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन बेहतर है?

Hero Glamour X Vs Honda CB125 Hornet: कीमत

Hero Glamour X को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके ड्रम वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपये, जबकि डिस्क वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपये है। वहीं, Honda CB125 Hornet को 1.12 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है।

Hero Glamour X Vs Honda CB125 Hornet: इंजन

Hero Glamour X में 124.7 cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर Sprint EBT इंजन दिया गया है, जो 11.3 hp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

Honda CB125 Hornet में 123.94 cc का 4-स्ट्रोक, SI इंजन दिया गया है, जो 11hp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

Hero Glamour X Vs Honda CB125 Hornet: फीचर्स

Hero Glamour X अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस बाइक में से एक है। यह क्रूज कंट्रोल पाने वाली पहली 125cc बाइक है। इसके अलावा, राइड-बाय-वायर और तीन राइडिंग मोड्स ईको, रोड और पावर दिया गया है। इसके साथ ही रियर पैनिक ब्रेक अलर्ट भी दिया गया है। इसके साथ ही फुल LED लाइटिंग, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, और फुली डिजिटल LCD क्लस्टर के साथ 60+ फंक्शन्स जैसे टैर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स, गियर इंडिकेटर, फ्यूल एफिशिएंसी डेटा, रेंज टू एम्प्टी, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

महिंद्रा XUV 3XO RevX बनाम हुंडई वेन्यू N लाइन : कीमत, इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है बेस्ट?

महिंद्रा XUV 3XO RevX बनाम हुंडई वेन्यू N लाइन महिंद्रा ने हाल ही में XUV 3XO के लिए नई RevX रेंज पेश की है जिसमें दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प हैं। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू N लाइन से है। XUV 3XO वेन्यू N लाइन से चौड़ाई ऊंचाई और व्हीलबेस में बड़ी है। XUV 3XO में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो वेन्यू N लाइन से अधिक पावर और टॉर्क देता है।

नई दिल्ली। महिंद्रा ने हाल ही में Mahindra XUV 3XO के लिए नई RevX रेंज को पेश की है। इसे दो दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इस लाइनअप में सबसे ऊपर RevX A वेरिएंट है, जो सबसे ज्यादा फीचर्स से भरा है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Venue N Line के N6 DCT वेरिएंट से देखने के लिए मिलेगा। हम यहां पर आपको इन दोनों (Mahindra XUV 3XO RevX A AT vs Hyundai Venue N Line N6 DCT) गाड़ियों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि कौन-सी कार बेहतरीन है?

Mahindra XUV 3XO RevX vs Hyundai Venue N Line: कीमत

Mahindra XUV 3XO RevX A AT: 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Hyundai Venue N Line N6 DCT: 12.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Mahindra XUV 3XO RevX vs Hyundai Venue N Line: डायमेंशन्स

महिंद्रा XUV 3XO करीब हर पैमाने पर आगे निकलती है, जबकि हुंडई वेन्यू N लाइन की लंबाई से थोड़ी छोटी है। ह चौड़ाई और ऊंचाई में काफी बड़ी है। इसके अलावा, इसका व्हीलबेस भी काफी लंबा है। यह सब मिलकर XUV 3XO को ज्यादा बड़ा केबिन दिया गया है।

Mahindra XUV 3XO RevX vs Hyundai Venue N Line: इंजन

महिंद्रा XUV 3XO RevX A में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह हुंडई वेन्यू N लाइन के 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की तुलना में 11 PS ज्यादा पावर और 58 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। XUV 3XO में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि वेन्यू N लाइन में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।

Mahindra XUV 3XO RevX vs Hyundai Venue N Line: फीचर्स

यह दोनों ही कई बेहतरीन और शानदार फीचर्स के साथ आती है। इनमें एलईडी हैडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज़ कंट्रोल और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन दोनों में 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने दी बड़ी राहत, इन वाहन चालकों के लिए किया टोल माफ

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य के तीन मुख्य हाइवे जिनमें मुंबई का अटल सेतु भी शामिल है अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल फ्री रहेंगे। नई ईवी पॉलिसी 2025 के अंतर्गत अटल सेतु समृद्धि एक्सप्रेसवे और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल से छूट मिलेगी। यह नियम 22 अगस्त 2025 से लागू होगा।

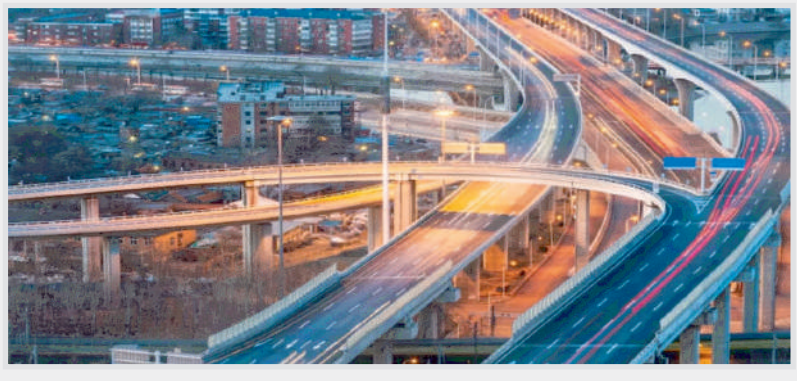

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख हाइवे अब टोल फ्री कर दिया है। इसमें मुंबई का अटल सेतु भी शामिल है। यह पुल बेहद अहम लिंक है, लेकिन इस पुल का इस्तेमाल करने पर भारी टोल टैक्स देना पड़ता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। नई EV पॉलिसी 2025 के तहत अटल सेतु पर ईवी गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।

ये हाइवे अब टोल फ्री

यह टोल माफी फिलहाल अटल सेतु कॉरिडोर के शिवाजी नगर और गावन कलेक्शन सेंटर्स पर लागू होगी। इससे पहले 31 जनवरी 2025 के एक रिजॉल्यूशन में सभी वाहनों के लिए टोल शुल्क 31 दिसंबर 2025 तक तय किया गया था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे बाहर कर दिया गया है। अटल सेतु के अलावा, समृद्धि एक्सप्रेसवे और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल छूट मिलेगी। पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य हाईवेज़ पर इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को टोल का सिर्फ 50% ही देना होगा।

किन वाहनों को मिलेगी छूट?

ऊपर बताए गए हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल फ्री किया गया है। इन इलेक्ट्रिक वाहनों में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (M1 कैटेगरी) इलेक्ट्रिक बसें (M3 और M4 कैटेगरी), चाहे वे स्टेट ट्रांसपोर्ट उपक्रम (STU) द्वारा संचालित हों या नॉन-STU ऑपरेटर्स द्वारा शामिल है। हालांकि, इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स को इस छूट में शामिल नहीं किया गया है।

कब से लागू होगा नियम?

22 अगस्त 2025 से यह छूट लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और इलेक्ट्रिक बसें इस पुल पर टोल फ्री होकर चल सकेंगी। यह फैसला महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जारी अधिसूचना में पुष्टि की गई है।

माइक्रोप्लास्टिक' आज जल-जीवन ही नहीं, हमारे भोजनचक्र में भी शामिल हो गया है

विजय गर्ग

समुद्र के बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक आगाह करते रहे हैं। मगर मनुष्य के निजी स्वार्थ, लापरवाही और अनदेखी करने की प्रवृत्ति के कारण समुद्री जीवन का दम घुट रहा। दुनिया के तीन अरब से अधिक लोग अपनी गुजर-बसर के लिए समुद्री जीवों पर निर्भर हैं, लेकिन इस संपदा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त और प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गैरकानूनी तरीके से मछलियां पकड़ने, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री जैव विविधता पर संकट गहराने लगा है। ऐसे में महासागरों के साथ ही वैश्विक आबादी के भविष्य को बचाने के लिए अब गंभीरता से प्रयास करना जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकारों, व्यावसायिक संरक्षकों और मछुआरों के लिए प्राथमिकताएं तय कर दिए जाने के बावजूद मुनाफे की होड़ में कोई भी अपने दायित्व को समझने और उस पर पूरी तरह अमल करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि एक तरफ अंधाधुंध तरीके से समुद्री जीवों का शिकार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर समुद्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। | जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। पेरिस समझौते में बढ़ते वैश्विक औसत तापमान में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित होने के बावजूद भू-मध्यसागर का तापमान बढ़ने की गति वैश्विक औसत से बीस फीसद अधिक हो चुकी है। महासागरों की सेहत बचाने के प्रयासों को वास्तव में बल मिलता है या फिर केवल संकल्पों का पुलिंदा, यह देशों और समुदायों द्वारा पेश किए जाने वाले उपायों और समाधानों पर निर्भर है। महासागरों के उपयोग में बड़ा बदलाव केवल मछलियां पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तरीकों से भी जुड़ा हुआ है। इस समय साठ फीसद से अधिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण का शिकार है। एक आकलन के मुताबिक, वर्ष 2040 तक प्लास्टिक का प्रदूषण वर्तमान स्थिति से करीब दोगुना हो जाएगा। हर वर्ष महासागरों में जाने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2.3 से 3.7 करोड़ टन तक हो जाएगी।"

'माइक्रोप्लास्टिक' आज जल-जीवन ही नहीं, हमारे भोजनचक्र में भी शामिल हो गया है। दुनियाभर के वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसा प्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जैव अपघटन मुमकिन हो। यानी गल कर प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाए। तोक्यो विश्वविद्यालय के 'रिकेन सेंटर फार इमर्जेंट मैटर' के शोधकर्ताओं ने एक नया पदार्थ तैयार किया है, जो बहुत जल्दी टूट जाता है और अपने पीछे कोई तलछट या अपशिष्ट नहीं छोड़ता। इससे पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक प्रदूषण को घटाने में मदद मिल सकती है।

शोधकर्ताओं ने अभी इस पदार्थ को व्यापारिक तौर पर पेश करने की योजना नहीं बनाई है। यह नया पदार्थ उतना ही मजबूत है, जितना कि प्लास्टिक, लेकिन जब इसे नमक के संपर्क में लाया जाता है तो यह अपने मूल घटकों में तुरंत टूट जाता है। उन घटकों को फिर प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले जीवाणु खत्म कर देते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया में हानिकारक 'माइक्रोप्लास्टिक' नहीं बनता है। वैश्विक संगठन वर्ष 2030 तक महासागरों के तीस फीसद हिस्से को संरक्षित करने का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक बार इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध ढंग से हटाने और पुनर्चक्रण में तकनीकी प्रगति अब जरूरी पहलू हो गया है। खास जोर महत्त्वाकांक्षी जलवायु योजनाओं के साथ समुद्रों में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई पर होना चाहिए, जो पेरिस जलवायु समझौते के 1.5 डिग्री लक्ष्य के अनुरूप हो। विश्वभर में जैसे-जैसे प्रवाल भित्तियों का क्षरण हो रहा है, वैसे ही मछलियों के भंडार दरक रहे हैं और समुद्री तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण,

पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश और समुद्री संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल महासागरों को लेकर अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। अप्रैल 2025 में समुद्री सतह का तापमान अपने दूसरे सबसे ऊंचे स्तर को छू गया था। कैरीबियाई, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में यह देखा गया कि चिंताजनक रफ्तार से बड़े पैमाने पर मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंच रहा है। वे सफेद पड़ती जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवों की करीब पच्चीस फीसद प्रजातियों को पोषित करती हैं।

ऐसे में पर्यटन तथा मछुआरा समुदाय के कारोबार ने नुकसान ही पहुंचाया है। इतना ही नहीं, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण निकलने वाले अत्यधिक ताप का करीब नब्बे फीसद हिस्सा महासागर ही अवशोषित करते हैं। यह मात्रा अब अपनी सीमाओं को छू रही है। इसी कारण कुछ वर्ष पूर्व विश्व व्यापार संगठन को अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ने पर लगाम लगाने के लिए एक समझौते के तहत सबसिडी पर रोक लगानी पड़ी थी। लंबे गतिरोध के बाद सदस्य देशों के बीच एक संधि पारित की गई, ताकि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री जीवन को संरक्षित किया जा सके, लेकिन समुद्र विज्ञानियों का मानना है कि केवल कागजी नीतियों से पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष उपजे इस जोखिम को दूर नहीं किया जा सकता है। इन नीतियों पर प्रभावी तरीके से अमल करने की जरूरत है।

वैश्विक जनजीवन को पोषित करने में महासागरों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वे जलवायु आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उनके संरक्षण के प्रयासों को गति देने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक संसाधनों का अभाव है। एक आकलन के मुताबिक, महासागरों के संरक्षण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए सालाना करीब 175 अरब डालर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ दस अरब डालर ही मुहैया हो पा रहे हैं। हर वर्ष करीब 1.2 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक महासागरों में समा जाता है। वैश्विक मछली भंडारण वर्ष 1970 में अपने सुरक्षित जैविक स्तर का 90 फीसद था, जो 2021 में घट कर 62 फीसद रह गया है। वर्ष 2017 के प्रथम महासागर सम्मेलन के बाद से अब तक हजारों स्वैच्छिक संकल्प व्यक्त किए जा चुके हैं, लेकिन नतीजे ढाक के तीन पात ही हैं। जैव विविधता संरक्षण पर वर्ष 2022 में हुए समझौते वर्ष 2030 तक कम से कम तीस फीसद समुद्री और पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर जोर दिया गया था। अब जरूरत है इस दिशा में प्रभावी तरीके से प्रयास करने और लक्ष्य हासिल करने की।

ग्यारह जून 2025 को फ्रांस में हुए जलवायु और पर्यावरण पर केंद्रित तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में एक आंकड़े ने सभी का ध्यान अपनी और खींचा है। इसमें कहा गया कि विश्व के कुल मछली भंडार का पैंतीस फीसद हिस्सा जिन तौर-तरीकों से पकड़ा जा रहा है, वे ठीक नहीं हैं। इस वजह से समुद्रों में मछलियों की संख्या में तेजी से गिरावट जारी है। अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ने, गहराता जलवायु संकट और समुद्री संसाधनों के कुप्रबंधन से महासागरों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। एक अध्ययन में 2,570 समुद्री मछली भंडारों पर केंद्रित डेटा विश्लेषण में बताया गया है कि कुल भंडारण में से एक तिहाई से ज्यादा मछलियों का शिकार किया जा रहा है। ऐसे में अब दुनिया भर में मत्स्य नीतियों पर नए सिरे पुनर्विचार की जरूरत है, ताकि वर्ष 2030 तक 30 फीसद महासागरीय क्षेत्र और पृथ्वी पर जलीय जीवों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट

"हिन्दी शिक्षकों की कमी : शिक्षा की आत्मा पर संकट"

भाषा की कमजोरी से पूरे शिक्षा तन्त्र पर असर

हरियाणा के विद्यालयों में अध्यापकों के सोलह हज़ार आठ सौ चालीस पद रिक्त हैं, जिनमें सर्वाधिक कमी हिन्दी विषय की है। हिन्दी केवल एक विषय नहीं बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा की आत्मा है। भाषा की कमजोरी से गणित, विज्ञान और अन्य विषयों की समझ भी प्रभावित होती है। सरकार ने अस्थायी नियुक्तियाँ तो की हैं, पर स्थायी भर्ती की गति धीमी है। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो शिक्षा का स्तर गिरने के साथ-साथ सांस्कृतिक जड़ों से भी दूरी बढ़ेगी।

- डॉ सत्यवान सौरभ

हरियाणा विधानसभा में हाल ही में प्रस्तुत आँकड़े यह चौंकाने वाले तथ्य सामने लाते हैं कि प्रदेश के चौदह हज़ार दो सौ पचानवे विद्यालयों में से सोलह हज़ार आठ सौ चालीस पद अध्यापकों के रिक्त पड़े हैं। यह केवल संख्या नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गहरी चिन्ता का विषय है। और सबसे अधिक चिन्ताजनक तथ्य यह है कि इन रिक्तियों में सर्वाधिक पद हिन्दी विषय के अध्यापकों के हैं।

हिन्दी केवल एक विषय नहीं, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा का आधार है। भाषा वह माध्यम है, जिसके ज़रिये बालक अन्य सभी विषयों को समझता है। यदि भाषा में पकड़ नहीं होगी तो गणित के सूत्र, विज्ञान के सिद्धान्त और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न भी अधूरे रहेंगे। इसीलिये हिन्दी अध्यापकों की भारी कमी केवल भाषा शिक्षा का संकट नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तन्त्र की कमजोरी का संकेत है।

किसी भी समाज की शिक्षा व्यवस्था उसकी मातृभाषा पर आधारित होती है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में हिन्दी करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हरियाणा जैसे हिन्दीभाषी राज्य में बच्चों के लिये पहली शिक्षा हिन्दी के माध्यम से ही होती है। यदि हिन्दी पढ़ाने वाले अध्यापक ही पर्याप्त नहीं होंगे, तो बच्चे न केवल भाषा में पिछड़ेंगे बल्कि अन्य विषयों को भी सही ढंग से आत्मसात नहीं कर पाएँगे।

आज स्थिति यह है कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक हज़ारों पद खाली पड़े हैं। हिन्दी की कक्षाएँ कई स्थानों पर या तो बिना अध्यापक के चल रही हैं या फिर अस्थायी अध्यापकों के भरोसे हैं। इसका सीधा प्रभाव बच्चों की लिखने-पढ़ने की क्षमता पर पड़ रहा है।

बच्चे शब्दों का सही उच्चारण, वाक्य निर्माण और व्याकरण में दक्ष नहीं हो पा रहे हैं। जब भाषा में पकड़ कमज़ोर होगी तो गणित, विज्ञान या इतिहास पढ़ते समय भी विद्यार्थी समझ नहीं पाएँगे। आज प्रत्येक परीक्षा में हिन्दी अनिवार्य है। अध्यापक की कमी से विद्यार्थियों की तैयारी अधूरी रह जाती है। भाषा केवल शिक्षा का माध्यम नहीं, संस्कृति का वाहक भी है। हिन्दी से दूरी का अर्थ है अपनी जड़ों से दूरी।

हरियाणा सरकार ने कौशल रोज़गार निगम के माध्यम से अब तक एक लाख उन्तीस हज़ार चार सौ तीस नियुक्तियाँ की हैं। इसमें आरक्षण और कोटा भी लागू किया गया है। किन्तु यह नियुक्तियाँ अधिकतर अस्थायी हैं। स्थायी भर्ती की गति अत्यन्त धीमी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दो हज़ार आठ सौ छप्पन पद रिक्त हैं। सहायकों के चार हज़ार आठ सौ नौ पद खाली हैं। स्नातकोत्तर अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और प्राथमिक स्तर पर भी हज़ारों पद खाली हैं। हिन्दी विषय में रिक्तियों की संख्या सबसे अधिक है।

सरकार के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी है, किन्तु अस्पष्ट नीतियों, आरक्षण विवाद, और प्रशासनिक विलम्ब के कारण बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब, निजीकरण का दबाव, सामाजिक मानसिकता और नीति-निर्माण में लापरवाही ने इस समस्या को और गम्भीर बना दिया है। विज्ञान और गणित को प्राथमिकता देते हुए हिन्दी को सहायक विषय की तरह देखा गया, जबकि यह शिक्षा की आत्मा है।

इस समस्या का समाधान केवल संख्यात्मक नियुक्तियों से नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भर्ती और प्रशिक्षण से ही सम्भव है। रिक्त पड़े हिन्दी अध्यापकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। अस्थायी व्यवस्था से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति अनिवार्य है। केवल नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं, अध्यापकों को समय-समय पर आधुनिक पद्धतियों और तकनीक का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। हिन्दी विषय को 'कम महत्त्वपूर्ण' मानने की मानसिकता बदली जानी चाहिए और ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से नियुक्ति होनी चाहिए।

आज जब भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना लेकर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, तब हिन्दी की महत्ता और भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक वैश्विक मंचों पर हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में यदि हमारे ही बच्चों को हिन्दी का बुनियादी ज्ञान नहीं मिलेगा तो यह विडम्बना ही होगी। हिन्दी केवल भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। इसे सुदृढ़ करना अर्थात् पूरे शिक्षा तन्त्र को सुदृढ़ करना है। यदि हम बच्चों को हिन्दी में सक्षम बनाएँगे तो वे अन्य सभी विषयों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएँगे।

हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में सोलह हज़ार आठ सौ चालीस रिक्त पद केवल प्रशासनिक आँकड़ा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की चिन्ता है। और हिन्दी विषय में सबसे अधिक कमी होना इस चिन्ता को और गहरा बना देता है। सरकार को चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया को तीव्र करे, स्थायी नियुक्तियाँ सुनिश्चित करे और भाषा शिक्षा को प्राथमिकता दे। यदि हिन्दी अध्यापकों की कमी पूरी नहीं की गई तो यह केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का भी नुकसान होगा।

हमें यह समझना होगा कि भाषा ही शिक्षा की आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर जितना निष्प्राण होता है, शिक्षा भी भाषा के बिना उतनी ही निर्जीव है।

जीव विज्ञान के समांतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

विजय गर्ग

इक्कीसवीं सदी की सबसे तीव्र और परिवर्तनशील क्रांति अगर कोई मानी जा रही है, तो वह है कृत्रिम मेधा, यानी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (एआइ) आज यह न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव सभ्यता के सोचने समझने, सीखने और कार्य करने के तरीकों को भी जड़ से बदल रही है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान इसके उपयोग से नए-नए अनुसंधान कर रहे हैं। मगर इन सबके बीच एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या कृत्रिम मेधा के बढ़ते प्रभाव के बीच जीव विज्ञान जैसे परंपरागत विषय की प्रासंगिकता बनी रहेगी? क्या जीव विज्ञान के विषय को एक 'कूट भाषा' से पूरी तरह संभाला जा सकता है? सवाल है कि कृत्रिम मेधा के इस युग में जीव विज्ञान की भूमिका है। उसकी उपयोगिता और सीमाएं क्या हैं तथा मानवीय और जिम्मेदारी का क्या स्थान है।

आज कृत्रिम मेधा का विस्तार जंगल की आग की तरह हो रहा है। मशीन और र इसके जटिल निर्माण तथा अन्य प्रणालियों से लैस तकनीकों ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना दिया है एआइ का उपयोग मशीनीकरण, ध्वनि या स्वर सहयोग, यातायात नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और संगीत रचना में भी किया जा रहा है। शिक्षा जगत में एआइ ने शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक नया संवाद स्थापित किया है। 'स्मार्ट' कक्षा, आभासी सहयोग और निजी स्तर पर सीखने के लिए समाधान की तलाश में विद्यार्थी अब अपनी रुचियों और जरूरतों के अनुसार पढ़ाई कर पा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा जांच और इलाज में मदद कर रही है, रोगों की पहचान कर रही है और शल्य चिकित्सा के लिए रोबोटिक सहयोग प्रदान कर रही है। इन सबके बीच जीव विज्ञान का क्षेत्र, जो मूलतः जीवन के अध्ययन से जुड़ा है, पर थोड़ा पीछे छूटता हुआ प्रतीत होता है। जीव विज्ञानः की जटिलता और इसकी नैतिक सीमाएं इसे बाकी तकनीकी क्षेत्रों से अलग । बनाती हैं। जीव विज्ञान केवल जीवों का अध्ययन नहीं, यह उन प्रक्रियाओं, घटनाओं, संबंधों और संरचनाओं की पड़ताल करता है, जो जीवन को संभव बनाती हैं। कोशिकाओं की बनावट, जीन की क्रियाएं, 'मेटाबोलिज्म', रोगों की उत्पत्ति और पर्यावरणीय प्रभाव इन सभी को समझे बिना न तो हम स्वयं को, न अपने समाज और न ही अपने ग्रह को सही ढंग से समझ से समझ सकते हैं।

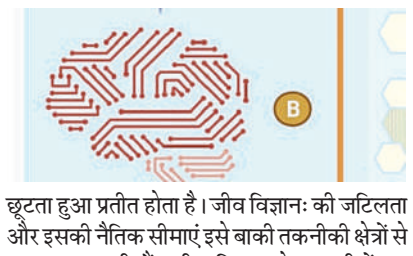

यह समझ हमें सिर्फ जानकारी के लिए लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न यह है कि क्या कृत्रिम मेथा कत्रिम मेथा जीव विज्ञान में में सहायक बन चुकी है। आज वैज्ञानिक कृत्रिम मेधा की मदद से जीनोमिका रा । जरिया बन स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। एक इंसान के डीएनए में लगभग तीन अरब 'बेस पेयर्स' होते हैं। इनका विश्लेषण करना अत्यंत जटिल कार्य है, लेकिन एआइ एल्गोरिदम के उपयोग से हम कोशिकाओं के लक्षणों को पहचान सकते हैं। उनके बहुरूपण का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और यहां तक कि व्यक्तिगत 'जीन प्रोफाइल' के अनुसार दवाएं विकसित की जा सकती हैं। दरअसल, दवा की खोज में भी कृत्रिम मेधा की मदद ली जा रही है। मशीनें अब यह अनुमान लगा सकती हैं कि कोई रासायनिक अणु किस बीमारी पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा।

भले ही कृत्रिम मेधा कई मायनों में उपयोगी है, पर इसके कुछ मूलभूत दोष और सीमाएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन, प्रयोगशाला से दूरी एआइ पूर्वानुमान लगा सकता है, लेकिन वह परीक्षण नहीं कर सकता। कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तभी मान्य होता है, जब वह प्रयोगशाला में दोहराया जा सके। आज भी कई एआइ प्रतिरूप प्रयोगशाला स्तर पर प्रमाणित नहीं हो पाते। दूसरा, नैतिकता की कमी एआइ संवेदनाओं से रहित होता है। वह 'क्या करना चाहिए' और 'क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए अगर एआइ एक दवा की सलाह देता है, जो किसी रोगी पर प्रभावी नहीं है, तो इसका दोष किस पर होगा? तीसरा, आंकड़ों का पूर्वाग्रह एआई वही सीखता और करता है, जो आंकड़ों में होता है। अगर आंकड़े असंतुलित या पक्षपाती हैं, तो परिणाम भी वैसा ही होगा चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों यह स्थिति घातक हो सकती है।

वहीं, जीव विज्ञान में मानवीय भागीदारी केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह नैतिक, भावनात्मक और व्याख्यात्मक भी होती है। उदाहरण के लिए- जब कोई वैज्ञानिक किसी नई दवा की खोज करता है, तो वह न केवल इसके परिणामों को देखता है, बल्कि यह भी सोचता है कि यह समाज पर क्या प्रभाव डालेगी। मनुष्य की जिज्ञासा, संवेदना और नैतिक जिम्मेदारी ही उसे मशीनों से अलग बनाती हैं·.

जिम्मेदारी और निष्पादन तक सीमित होती है। ऐसे में । एआइ और मनुष्य के संबंध प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहकारी होने चाहिए। कृत्रिम मेधा को एक सहायक उपकरण की तरह उपयोग किया जाना चाहिए, न न कि किसी अंतिम निर्णयकर्ता की तरह कृत्रिम मेधा द्वारा प्रदान की गई सटीकता और गति अगर मनुष्य की समझ, अनुभव और नैतिकता से जुड़ जाए, तो विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू सकते। * लेकिन की भूमिका हमेशा मनुष्य के पास होनी के पास होनी चाहिए। कृत्रिम मेधा और जीव विज्ञान के इस बढ़ते संवाद से शिक्षा प्रणाली का रूप भी रूप भी बदल रहा है। पारंपरिक कक्षाएं अब साइबर साइबर प्रयोगशाला और संवादात्मक जैविक प्रतिरूप के माध्यम से बदल रही हैं। इसके उपयोग से अब विद्यार्थियों को जटिल जैविक प्रक्रियाओं जैसे प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, जीन अभिव्यक्ति आदि को त्रिआयामी और एनीमेशन के जरिए देखने और समझने का अवसर मिल रहा है। इससे न केवल गहराई से समझ विकसित हो रही है, बल्कि सीखने और रचनात्मकता भी बढ़ रही है। अब विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचि और सीखने की शैली के के अनुसार पाठ तैयार होते हैं। साथ ही शिक्षक अब डेटा-विश्लेषण की मदद से यह पहचान सकते हैं कि किस विद्यार्थी को किस विषय में अधिक सहायता की आवश्यकता है और उसी शिक्षण की नीतियां अपनाई जा सकती हैं।

¨शिक्षा में यह तकनीकी एकीकरण अगर सही दिशा और संतुलन के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में नई पीढ़ी को और अधिक आत्मनिर्भर, जिज्ञासु और व्यावहारिक बना सकता है। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है कि कृत्रिम मेधा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। इस साधन को मानवीय समझ, संवेदना और मार्गदर्शन के साथ जोड़ना ही शिक्षण की सफलता की कुंजी होगी। कृत्रिम मेथा एक शानदार तकनीक है, जिसने विज्ञान को नई दिशा दी है, लेकिन जब बात जीव विज्ञान की आती है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह विषय केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन की समझ, भावनाओं और जिम्मेदारियों से जुड़ा है। इसलिए कृत्रिम मेधा जीव विज्ञान को अधिक तेज, सटीक और गहन बना सकती है, लेकिन वह कभी भी मानवीय अंतर्दृष्टि की जगह नहीं ले सकती।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

घरेलू खपत और आत्मनिर्भरता की राह

विजय गर्ग

इस समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए जा रहे शुल्क के डर से दुनिया के अधिकांश देश अमेरिका के सामने झुक कर उसकी व्यापार शर्तों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भारत अमेरिका के साथ कारोबार समझौते के तहत अपने करोड़ों किसानों और मछुआरों के हितों के मद्देनजर बिना झुके अपनी शर्तों के साथ अडिग है। ऐसे में पूरी दुनिया यह देख रही है कि भारत अमेरिका के ऊंचे शुल्क का अपनी मजबूत घरेलू खपत के हथियार से मुकाबला कर रहा है। बीते पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में व्यापक सुधार की घोषणा की और उसके शीघ्र क्रियान्वयन का संकेत दिया। उम्मीद है कि इससे भारत में घरेलू खपत तेजी से बढ़ेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए पचास फीसद शुल्क से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर प्रकाशित वैश्विक रपटों में कहा जा रहा है कि भारत की घरेलू खपत मजबूत है। ऐसे में भारत की विकास दर में किसी चिंताजनक गिरावट की आशंका नहीं है। हाल ही में 13 अगस्त को वैश्विक रेटिंग एजंसी 'एसएंडपी' ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर पचास फीसद ऊंचे शुल्क लगाने से उसकी आर्थिक तरक्की पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। भारत की 'सावरेन रेटिंग' का नजरिया अभी भी सकारात्मक बना रहेगा। चूँकि भारत एक निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था नहीं है, ऐसे में उसे फिलहाल शुल्क संबंधी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 'एसएंडपी' का मानना है कि भारत की विकास दर

चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 फीसद रहेगी। इसी तरह सात अगस्त को 'मार्गन स्टेनली रिसर्च' के एक विश्लेषण में भी भारत की घरेलू मांग मजबूत होने की बात कही गई है।

इस समय भारत की विकास दर को मजबूत आंतरिक घरेलू आधार मिला हुआ है। अब इसे लगातार आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। यह भी कहा गया है कि भारत की विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर से दोगुना से । भी अधिक रहने का अनुमान है। इसी तरह रेटिंग एजंसी 'क्रिसिल' ने अपनी रपट में कहा है कि भारत में घरेलू खपत में सुधार, भरपूर खाद्यान्न उत्पादन, बेहतर मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, महंगाई में कमी, सस्ते कर्ज और अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक संकेतों । के कारण इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 6.4 फीसद के स्तर पर होगी।

पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने लोकसभा में कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्वल केंद्र मानती हैं। अमेरिका ने जो शुल्क लगाए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों, निर्यातकों और उद्योगों के हितों की रक्षा करेगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेज विकास के लिए वित्तीय, श्रम और कृषि सुधारों को लागू करने की डगर पर बढ़ना अब जरूरी है।

गौरतलब है कि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई घटने से भी घरेलू बाजार में खपत को बढ़ावा मिल रहा है। खुदरा महंगाई घट कर आठ वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है। सस्ते कर्ज से उद्योग कारोबार में उत्साह है। कृषि क्षेत्र में रेकार्ड उत्पादन, मानसून की

अच्छी प्रगति, पर्याप्त जलाशय स्तर और मजबूत खरीफ बुवाई से सकारात्मक परिदृश्य दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, नवउद्यम, नवोन्मेष, तेजी से बढ़ता बाजार और सेवा क्षेत्र की ऊंचाइयां ऐसी शक्तियां हैं, जो दुनिया के देशों को भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

खुदरा महंगाई का अनुमान आरबीआइ ने घटाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमान 3.7 फीसद से घटा कर 3.1 फीसद कर दिया है। जून 2025 में खुदरा महंगाई घट कर 2.1 फीसद पर आ गई। मई में खुदरा महंगाई दर 2.82 फीसद रही। इतना ही नहीं, जून में थोक महंगाई दर भी 20 महीने में पहली बार ऋणात्मक हुई। यह घट कर 0.13 फीसद रह गई। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों गिरावट के साथ-साथ विनिर्मित उत्पादों की लागत में भी कमी आई। मई थोक महंगाई दर 0.39 फीसद थी। जहां महंगाई में तेज गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए काफी लाभप्रद है, वहीं भारत में सस्ते कर्ज से भी घरेलू उपचार में खपत और आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी। विगत छह जून को रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए रेपो रेट में 50 आधार अंकों यानी 0.50 फीसद की कटौती का एलान किया। अब रेपो रेट छह फीसद से घट कर 5.5 फीसद हो गई है। इस वर्ष 2025 में फरवरी से अब तक लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी एक फीसद की बड़ी कटौती करते हुए इसे तीन फीसद पर ला दिया है।

निश्चित रूप से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को नया रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए समझौते अहम हैं। भारत को संयुक्त अरब और आस्ट्रेलिया के साथ समझौते से लाभ हुआ है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित एफटीए पर 24 जुलाई को हस्ताक्षर हुए। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में दस जुलाई को भारत में स्विटजरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी ने कहा कि भारत और चार सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौता अक्तूबर 2025 से लागू हो जाएगा। इन सबके साथ-साथ भारत-आसियान के बीच मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चर्चा जारी है। आसियान में ब्रुनोई, कांबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू वृद्धि को सहारा देने के लिए अब नीतिगत समर्थन बढ़ाना जरूरी होगा। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी उद्योग कारोबार को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करना जरूरी होगा। उम्मीद करें कि सरकार घरेलू खपत के इजाफे के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। यह भी उम्मीद है कि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर थोपे गए पचास फीसद शुल्क की चुनौती से मुकाबला करने के लिए घरेलू बाजार की खपत को हर संभव तरीके से और मजबूत बनाते हुए विकास दर को ऊंचाई पर बनाए रखेगी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री का पत्रकार सम्मेलन

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने रांची पहुंचते ही कहा कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के बाद बातचीत करेंगे. सीएम हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया गया. उनकी गरिमा को कुचला गया. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर धन शोधन के आरोप लगाने वाले संवैधानिक पदाधिकारी उनकी गरिमा के उल्लंघन में शामिल हैं. उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. वे कांके रोड स्थित सीएम आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे. मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य मौजूद थे.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है. इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारी में जुटे हैं. इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी रांची पहुंचे है . वे वोटरों से व्यक्तिगत संपर्क भी कर रहे हैं. झारखंड में उनका स्वागत करते हैं. चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी. 9 सितंबर 2025 को मतदान होना . इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डीनेज़ प्रेस वार्ता के मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, लोक सभा सांसद रघुराम रेड्डी, सांसद सिंहभूम जोबा मांझी, सुखदेव भगत एवं कालीचरण मुंडा तथा राज्यसभा सांसद महुआ माजी एवं सरफराज अहमद मौजूद थे.

आधुनिकता के अंधी दौर में सामाजिक पतन की शुरुआत

नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी

इंसानों में जैसे- जैसे सोचने व समझने की प्रवृति जागृत होती गई, वैसे - वैसे इंसानों के अंदर छल कपट की प्रवृति भी जागृत होती गई । इंसान जब तक कंद मूल या आखेट पर निर्भर था, तब तक इंसान के अंदर इस तरह की पाशविक प्रवृति नही थी । जबसे इंसान अन्न का उत्पादन करने लगा, उस समय से इंसान का वास्तविक स्वरूप ही बदल गया । जमीन को लेकर इंसानों में जंग लड़ने की स्थिति पैदा हो गई । ज्यादा से ज्यादा जमीन का टुकड़ा उसके कब्जे में रहे, वह अब इंसानों का ध्येय बनकर रह गया और जो आज तक कायम है । जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया, तैसे- तैसे मनुष्य और असभ्य होता चला गया । आज हम अपने आप को बहुत आधुनिक और प्रगतिशील समझ रहे हैं लेकिन वास्तविकता ये है कि हम दिन प्रतिदिन गर्त में डूबते जा रहे हैं । आज पूरे विश्व में अराजकता का माहौल है । आज रूस और यूक्रेन युद्ध में रोज न जाने कितने बेगुनाहों की जान जा रही है । उसी तरह गाजा पट्टी में कितने मासूमों की जान जा रही है । आज पूरा विश्व सभ्यता के किस मोड़ पर खड़ा है, इसको ध्यान में रखकर सोचना होगा । युद्ध के नित्य नए नए ठिकाने ढूंढे जा रहे हैं । रोज मानवता शर्मसार होती जा रही है । आज भारत में ही आये दिन कहीं न कहीं से दिल दहला देने वाली खबर आती है । प्रेम प्रसंग में रोज एक न एक कत्ल का खुलासा होता है । आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करना । दरअसल आज समाज किस दिशा में जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है । आधुनिकता के इस दौर में हम समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं और इसका खामियाजा क्या होगा, इस पर गौर करने की जरूरत है ।

किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं और कौन सा पहलू उचित है और कौन सा अनुचित, इसका फैसला हमें ही करना होगा । आज नारियाँ स्वतंत्र होती जा रही हैं और ये अच्छी बात है लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं । समाज में व्यभिचार अपने चरम सीमा पर है । इसमें किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।

इसके लिए स्त्री या पुरुष समान रूप से जिम्मेदार हैं ।जब समाज स्वछंद होगा तो समाज में इस तरह की विकृति जरूर आएगी । इसलिए ये समाज को एक सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने आप को कहाँ तक स्वछंद रखें । ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जिसमें कोई खून खराबे की खबर नहीं आती हो । आज इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है । सच तो ये है कि आज मानवता नाम की कोई चीज ही नही रह गई । समाज की जो आज स्थिति है उसमें ये आकलन करना मुश्किल है कि हम सभ्य समाज में रह रहे हैं या असभ्य समाज में ।

किसी जमाने में संस्कार नाम की कोई चीज हुआ करती थी ,आज उसका सर्वथा लोप हो चुका है । पहले पश्चिमी देशों में इसका खात्मा हुआ और धीरे धीरे पूर्व के देशों में इसका प्रभाव होता गया है । भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा । दुनिया भर में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ कुछ नहीं तो संस्कारों की दुहाई अवश्य दी जाती रही है लेकिन दुर्भाग्यवश आज भारत में ही संस्कार अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है । दरअसल इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं । आजादी मिलने के बाद हम इतने उच्छृंखल हो गए कि हमें इसका ध्यान ही नहीं रहा कि आगे इसके दुष्परिणाम भी होंगे । हमने अपने बच्चों की परवरिश में ढील देनी शुरू कर दी । गार्जियनशिप का रोल ही खत्म हो गया । आज बच्चे न अपने माँ - बाप की सुनते हैं और न शिक्षकों की । इसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चों में अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है । भौतिकता के क्षेत्र में हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अवश्य कर रहे हैं लेकिन अपने अच्छे संस्कारों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं । दरअसल हम आधुनिकता की कीमत चुका रहे हैं । एक तरफ तो हम मंदिर- मस्जिद भी जाते हैं वहीं दूसरी ओर वहाँ से क्या लेकर समाज में जाते हैं, इसका आपको पता ही नही रहता । मंदिर-मस्जिद केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है अपितु उन जगहों से आपको अच्छे इंसान बनने की सीख मिलती है लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति इस बात को समझता होगा । आज दुनिया में बहुत सी लड़ाइयां ही धर्म के नाम पर लड़ी जा रही हैं । अगर लोगों में धार्मिक सहिष्णुता हो जाये तो आधी दुनिया की लड़ाई ही खत्म हो जाये । उसी तरह दैनिक जीवन मे शुचिता पैदा हो जाये तो समाज में व्याप्त व्यभिचार स्वत: खत्म हो जाएगा ।

दरअसल इंसान को केवल अपने जज्बात पर काबू पाने की आवश्यकता है । ये काम असंभव नही है । बच्चों को अगर शुरुआत से ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए तो इन समस्याओं का समाधान मुमकिन है । इसके पूरे विश्व को सामाजिक स्तर पर काम करना होगा । ये एक दिन में नहीं हो सकता है लेकिन एक दिन अवश्य हो सकता है । इसके लिए समाज को दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा । आज विश्व को युद्ध की जरूरत कदापि नहीं है । आज पूरे विश्व को विस्तारवादी नीति को छोड़ना होगा । रूस और चीन को सबसे पहले इस नीति पर कार्य करना होगा । दरअसल भारत को विश्व में अमेरिका और रूस की तरह अग्रणी राष्ट्र बनकर उभरना होगा । हमें परमाणु क्षमता और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होना पड़ेगा । जबतक भारत सशक्त नहीं होगा, तबतक विश्व में शांति सम्भव नहीं है ।

विश्व में एक जिम्मेदार राष्ट्र का सशक्त होना जरूरी है । एक समय था जब अमेरिका की तूती बोलती थी लेकिन आज ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका की मिट्टी पलीद हो चुकी है । अब उसकी विश्व में कोई सुनने वाला नहीं है । यूक्रेन एवं रूस के युद्ध को मिनटों में खत्म करवाने का दावा टाँय- टाँय फिस्स हो गया । इजराइल और हमास के बीच के युद्ध को नहीं रुकवा सका । पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रुकवाने की बात भी ट्रम्प का बड़बोलापन साबित हुआ । अलास्का में क्या हुआ, ये जग जाहिर है । इसलिए अब अमेरिका का विश्व में कोई मोल नहीं रह गया है और ट्रम्प अपने बाकी के कार्यकाल में अमेरिका की और मिट्टी पलीद करेगा । भारत को इसी कालखंड में अपने आप को कूटनीतिक स्तर पर एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में स्थापित करना होगा । आज हमें रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा । अमेरिका का टैरिफ गया तेल लेने । इससे हमें डरने की जरूरत नही है । इस सबके लिए भारत की कूटनीति काफी कारगर साबित हो रही है ।

अब तक जिले में पशुओं के लिए 142 क्विंटल साइलेज और लगभग 800 क्विंटल चारा पहुँच चुका है-उपायुक्त

अमृतसर 30 अगस्त (साहिल बेरी)

बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए अजनाला में तीन राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें अब तक 300 लोग शरण ले चुके हैं। इनमें से कुछ परिवार अपने निकट संबंधियों के यहाँ चले गए हैं और कुछ नए प्रभावित परिवार इन शिविरों में शरण ले रहे हैं। रेडक्रॉस की मदद से इन परिवारों के रहने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पशुपालन विभाग को अब तक पशुओं के लिए 142 क्विंटल साइलेज (सूखा चारा) और लगभग 800 क्विंटल चारा प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 500 क्विंटल चारा और लगभग 100 क्विंटल हरा चारा वितरित किया जा चुका है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने बताया कि पूरा प्रशासन बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए दिन-रात काम कर रहा है और पूरे मानसून के दौरान भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ हैं। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए तैनात एनडीआरएफ टीमों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि ये टीमें पूरी तत्परता से अपना काम कर रही हैं और लोगों को बचा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राशन, पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा आदि उपलब्ध करवाने के लिए रेड क्रॉस अमृतसर और मार्केट कमेटी अजनाला के कार्यालय में जा सकती है। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए श्री दविंदर ठाकुर के मोबाइल नंबर 9877076017 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अमनदीप कौर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अमनदीप कौर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए दाना मंडी अजनाला, भाला गांव शुगर मिल और गुरुद्वारा गुरु का बाग में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पशुओं के लिए दाना मंडी अजनाला में भी एक विशेष राहत शिविर स्थापित किया गया है, जहाँ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के अलावा एक पशु चिकित्सक की भी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोग किसी भी सहायता के लिए राहत कार्य दाना मंडी चोगावां रोड अजनाला के हेल्पलाइन नंबर 8437653157, राहत शिविर भाला गाँव शुगर मिल के हेल्पलाइन नंबर 7528043152 और राहत शिविर गुरुद्वारा गुरु का बाग के हेल्पलाइन नंबर 8264265504 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तहसील मजीठा के अधीन आते गाँवों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 79737-39979 है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हर समय उनकी मदद के लिए मौजूद है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से अपील करते हुए कहा कि वे इन राहत शिविरों में शरण ले सकते हैं और उनके लिए भोजन और पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 0183-2229125 और अजनाला में हेल्पलाइन नंबर 01858-245510 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति में इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन उनकी हर संभव मदद कर सके।

बाढ़ पीड़ितों को योजनाबद्ध ढंग से राहत सामग्री भेजने के लिए अजनाला सक्की पुल पर सूचना केंद्र खोला गया: जस्करण बंदेशा

पूर्व सरकारों ने कथित घोटालों की बजाय अगर धुसी बांध मजबूत बनाए होते तो आज बाढ़ की समस्या नहीं होती : बंदेशा

बाढ़ पीड़ितों की ग्राउंड जीरो पर मदद, श्री केजरीवाल और श्री मान का नेक मानवता कार्य का प्रमाण : बंदेशा

अजनाला/अमृतसर, (साहिल बेरी) –

आम आदमी पार्टी लोकसभा हलका अमृतसर के इंचार्ज और पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के नव नियुक्त उपाध्यक्ष श्री जस्करण बंदेशा ने बाढ़ पीड़ितों के साथ हमदर्दी जताते हुए पार्टी की ओर से पीड़ितों को उचित सहायता पहुँचाने की जारी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोकसभा अमृतसर के सभी पदाधिकारी, सक्रिय वालंटियर, पार्टी के महिला, किसान समेत सभी विंगों के कार्यकर्ता अपने समर्थकों और हमदर्दों की भरपूर भागीदारी से निःस्वार्थ सेवा भावना के साथ हलका अजनाला में रावी दरिया और सक्की नाले में आई प्राकृतिक बाढ़ से प्रभावित किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों और अन्य वर्गों के पीड़ितों तक पहुँचकर आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। खराब मौसम और बारिश के बावजूद सुबह से देर शाम तक डटे रहते हैं।

अब बाढ़ प्रभावित गाँवों में योजनाबद्ध ढंग से पीड़ितों की ज़रूरत के अनुसार राहत सामग्री पहुँचाने के लिए पार्टी ने ज़िले भर से आ रही राहत टीमों की सुविधा हेतु अजनाला शहर के सक्की पुल के पास डेरा रोड पर बाकायदा राहत सामग्री सूचना केंद्र खोल दिया है।

राहत सामग्री सूचना केंद्र की औपचारिक शुरुआत करते हुए लोकसभा हलका इंचार्ज और उपाध्यक्ष श्री बंदेशा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों का दर्द बाँट रहे हैं। पीड़ितों की मदद के लिए सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में दिन-रात लगे हुए हैं। वहीं सेना और बीएसएफ भी बाढ़ग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। यह सब श्री केजरीवाल और मुख्यमंत्री मान के नेक मानवता कार्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत पिछली सरकारों के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से केवल हवाई सर्वेक्षण करते रहे जबकि मुख्यमंत्री मान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ की तबाही को देखा और उसी दौरान अपने हेलीकॉप्टर को मौके पर फँसे लोगों को निकालने के लिए समर्पित कर दिया।

श्री बंदेशा ने कहा कि वह ऐसे संवेदनशील समय में राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन जब उन्होंने प्रभावित क्षेत्र अजनाला का दौरा किया तो यह देख अफसोस हुआ कि पूर्व सरकारों ने प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए कार्य करने की बजाय मौजूदा बाढ़ की स्थिति के लिए सीधा मान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ितों की कीमत पर खोखली राजनीति की। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और सांसद गुरजीत सिंह औजला से वह अवश्य पूछना चाहते हैं कि जब उनकी पार्टियाँ राज्य और केंद्र की सत्ता में थीं तो धुसी बांधों और नदियों-नालों के किनारों की मज़बूती के लिए जारी अरबों रुपये की राशि का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। यदि धुसी बांध स्टील और लोहे से ऊँचे-चौड़े और मज़बूत बनाए गए होते तो आज पंजाबवासियों को बाढ़ की इस समस्या का दुःख नहीं झेलना पड़ता।

इस अवसर पर गुरप्रताप सिंह संधू (ज़िला प्रधान देहात), प्रभावीर सिंह बराड़ (ज़िला प्रधान शहरी), अरविंदर भट्टी (मीडिया जोनल प्रभारी), हरप्रीत सिंह सोहल, चेयरमैन सतपाल सोखी, सुखबीर कौर (जोनल प्रधान महिला विंग), कमना आनंद (ज़िला प्रधान शहरी), बलविंदर सिंह काला, किरपाल सिंह, मास्टर मोहन लाल भगत आदि वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

नागरिक परिक्रमा (संजय पराते की राजनैतिक टिप्पणियां)

1. जस्टिस नागरत्ना की असहमति पर गौर करना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल एम. पंचोली को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।कॉलेजियम ने न्यायाधीश पंचोली को पदोन्नत करने की सिफारिश 4-1 के बहुमत से की है। कॉलेजियम में पांच सदस्य है : भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जेके माहेश्वरी और बी वी नागरत्ना। जस्टिस नागरत्ना ने पंचोली के नाम का विरोध किया है। न्यायमूर्ति पंचोली की नियुक्ति पर अपनी कड़ी असहमति दर्ज करते हुए उन्होंने कहा है कि पंचोली की नियुक्ति न केवल न्याय प्रशासन के लिए "प्रतिकूल" होगी, बल्कि कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को भी खतरे में डालेगी।

हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के जरिए होती है। यह सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी निर्णय यदि सर्वसम्मति से नहीं हो सकता, तो फिर बहुमत से हो। लेकिन इस सिद्धांत का पालन ₹कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को खतरे में डालकर₹ करना कितना उचित होगा? न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति से यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने असहमति के जो बिंदु उठाए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति का विचार सबसे पहले मई में सामने आया था और उनके सहित कॉलेजियम के दो सदस्यों ने अपनी आपत्तियाँ व्यक्त की थीं। इन आपत्तियों के मद्देनजर पंचोली का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। फिर तीन माह में ऐसा क्या हुआ कि फिर यही नाम सामने आ गया?

पंचोली गुजरात से आते हैं। यह सामान्य सिद्धांत है कि सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि गुजरात का प्रतिनिधित्व दो न्यायाधीश कर रहे हैं। ऐसे में फिर से गुजरात को ही सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व देने से संतुलन बिगड़ेगा, जबकि अखिल भारतीय वरिष्ठता क्रम में पंचोली का स्थान 57वां है।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली की गुजरात उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण को भी ₹असामान्य₹ बताया है और कहा है कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। यह ₹असामान्य₹ क्या था, इसे जानने के लिए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कॉलेजियम से आग्रह किया है कि 2023 के स्थानांतरण से संबंधित गोपनीय कार्यवृत्त मंगवाए जाएँ और उनका अवलोकन किया जाए। स्पष्ट है कि 'गोपनीयता' के कारणों से वे इस असामान्य को सार्वजनिक नहीं कर रही है। लेकिन इससे साफ संकेत मिलता है कि यह ₹असामान्य₹ किसी भी रूप में सामान्य नहीं है और यह एक न्यायाधीश के रूप में उनकी कार्यप्रणाली, आचार व्यवहार और चरित्र से जुड़ता है, जो एक न्यायाधीश के रूप में उनकी खामियों की ओर भी इंगित करता है। इसीलिए अपनी असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि यदि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति होती है, तो वे अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हो सकते हैं, जो उनके अनुसार संस्थान (न्यायपालिका) के हित में नहीं होगा।

जस्टिस नागरत्ना की न्यायिक निष्पक्षता निर्विवाद और काबिले तारीफ है। इसीलिए उनकी असहमति पर गौर करना जरूरी है। मोदी राज में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर हमले हो रहे हैं और उनकी स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा है, इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट पर ही देश की आम जनता का भरोसा बचा हुआ है। आज जब संघी गिरोह और उसके प्रतिनिधि के रूप में सत्ता में बैठी भाजपा द्वारा संविधान और उसके मूल्यों पर तीखे हमले हो रहे हैं, संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार के रूप में, संविधान बचाने की लड़ाई में, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और पूरे देश की आशा सुप्रीम कोर्ट पर ही टिक जाती है। सुप्रीम कोर्ट के ढहने के बाद इस बाबा साहेब आंबेडकर की अगुआई में बने इस देश के संविधान को भी ढहने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए यदि पंचोली में ऐसा कुछ ₹असामान्य₹ है, जिसके चलते तीन माह पहले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति के विचार को खारिज कर दिया था, तो उनकी नियुक्ति को तब तक वैध नहीं माना जा सकता, जब तक कि पंचोली अपनी ₹असामान्यता₹ की स्थिति से बाहर नहीं आ जाएं। इसलिए तीन माह बाद ही उनकी खारिजी को दरकिनार करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने के फैसले को, बहुमत से ही सही, हरी झंडी देना 'पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहे' होने का संदेह तो जरूर पैदा करता है। इस संदेह से तो यही सहज निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 57 लोगों की वरिष्ठता को दरकिनार कर की जा रही इस नियुक्ति का आधार योग्यता तो हो नहीं सकती, इसलिए यह नियुक्ति राजनैतिक है। यदि ऐसा है, तो हमारे देश का संविधान और न्यायपालिका का भविष्य खतरे में है।

2. केरल में भाजपा का खाता खोलने का सच

केरल राज्य का इतिहास है कि इस राज्य की विधानसभा पर बारी-बारी से कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ़ और माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा ने कब्जा किया है। पिछला विधानसभा चुनाव ही इसका अपवाद है, जब माकपा के मोर्चे ने लगातार दूसरी बार विजय प्राप्त की है। इसी प्रकार, लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा भी दोनों मोर्चों के बीच ही हुआ है। इसलिए यह माना जा सकता है कि केरल राज्य कांग्रेस और माकपा का गढ़ है। इनके बीच किसी तीसरे दल की उपस्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में केरल के त्रिशूर लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी सुरेश गोपी ने विजय प्राप्त की थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा तीसरे स्थान पर थी। त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र को माकपा का गढ़ माना जाता है। इसलिए इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की विजय को गोदी मीडिया द्वारा माकपा के गढ़ में भाजपा के सेंध के रूप में प्रचारित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान ही माकपा की त्रिशूर जिला समिति के बैंक खाते को चुनाव आयोग द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। तब माकपा ने आरोप लगाया था कि भाजपा को जीताने के लिए ही चुनाव आयोग ने यह काम किया है, ताकि चुनाव प्रचार के लिए माकपा अपनी धनराशि का उपयोग न कर सके।

लेकिन राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान दक्षिण भारत के एक विधानसभा के अध्ययन के बाद वोट चोरी के जो प्रामाणिक आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं, उसके बाद देश भर की मतदाता सूचियों के अध्ययन से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वे आश्चर्यजनक है और इस बात की पुष्टि कर रहे है कि वोट चोरी का यह पैटर्न पूरे देश में अपनाया गया है। 'द न्यूज मिनट' ने भी त्रिशूर लोकसभा सीट का अध्ययन किया है। इसने रिपोर्ट से पता चलता है कि माकपा के बैंक खातों को ब्लॉक करने के साथ ही यहां भी फर्जी वोटिंग का यही पैटर्न अपनाया गया था।

'द न्यूज़ मिनट' की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि यहाँ पांच साल में 1.46 लाख मतदाता जोड़े गये और 2019 की चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाले सुरेश गोपी को जितवाया गया। बीजेपी के नेताओं के कथित रिश्तेदार और खाली बिल्डिंग के पते पर लोगों के मतदाता कार्ड बनाये गये। कमाल की बात यह है कि जिन लोगों को जोड़ा गया, उनमें से 99% लोग अब त्रिशूर में नहीं रहते। सुरेश गोपी के ड्राइवर अजय कुमार के पते पर ही दर्जनों वोट पड़े, जिनका कोई रिकार्ड अब नहीं है। इसी तरह हजारों वोट बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं के घर से पड़े, जिनका कोई रिकार्ड ढूढ़ने से नहीं मिल रहा है।

सुरेश गोपी के रूप में भाजपा की विजय को चिन्हित करने के लिए अब उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया गया है। तो यह है, केरल में संघीयों के खाता खोलने का सच। लगता है कि अब किसी भी सीट की छानबीन कर ली जाएं, भाजपा की जीत में ऐसे ही फर्जीवाड़े उजागर होंगे। यह फर्जीवाड़ा भाजपा की जीत को अवैध बना देता है। भाजपा भले ही तीन-साढ़े तीन साल और सत्ता में रह लें, आम जनता की नजरों में अब उसका ऊपर चढ़ना मुश्किल है। वोट चोर, गद्दी छोड़ का विपक्ष का नारा एक मजबूत अर्थ ग्रहण करता जा रहा है।

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।

केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में सरायकेला जिले मे 'दिशा' बैठक - योजनाओं की मंदगति , खामियां उजागर

पूर्व उपायुक्तों के समय योजनाओं का प्रगति रिपोर्ट मिडिया को उपलब्ध होता था, दशकों से पत्रकार सम्मेलन बंद, नतीजा –जिला विकास की गती धीमी!

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला ,जिला समाहरणालय सभागार में संजय सेठ केंद्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता दिशा की बैठक हुई । इस बैठक का मुल उद्देश्य संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा सदस्यों और स्थानीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित कर कुशल विकास सुनिश्चित करने वाली एक समिति है। जो निगरानी भी करती है , परन्तु आज के बैठक में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में विकास का चाल कछुए की मंद गति से कैसे चल रही है यह अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय मंत्री के उद्गार से जगजाहिर हो गया।

बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की क्रमवार समीक्षा की गई। साथ ही पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा भी हुई ।

केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत, खाद्य आपूर्ति, पेयजल एवं स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, केसीसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पथ निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिन योजनाओं की प्रगति धीमी पाई गई, उनमें सुधारात्मक कदम उठाते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया।

आगामी 22 फरवरी (दुर्गा पूजा से पूर्व) तक जिले के सभी खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मती अथवा प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में जर्जर तार एवं खंभों की समस्या को प्राथमिकता पर दुरुस्त कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आगामी 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को जिले में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाए।विगत 3-4 माह से हो रही लगातार वर्षा से प्रभावित परिवारों का आकलन कर उन्हें सरकार की योजनाओं से शीघ्र जोड़ते हुए लाभ उपलब्ध कराया जाए।विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निपटारा तय समयावधि में किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लंबित कार्यों में तेजी लाई जाए तथा लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर कार्रवाई की जाए।हर-घर नल-जल योजना से सभी गाँव-टोला को जोड़ा जाए।खराब चापाकल एवं जलमीनारों की मरम्मती हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। औधोगिक संस्थानों से संबंधित प्रदूषण संबंधी शिकायतों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को आवास योजना सहित अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए।

सड़क सुरक्षा के संदर्भ में मंत्री सेठ ने कहा कि जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्ययोजना बनाई जाए।सभी पदाधिकारी इसके अनुरूप कार्य करें एवं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खराब सड़कों की मरम्मती शीघ्र कराई जाए।

सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।जिन सड़क निर्माण योजनाओं में संवेदकों द्वारा अनावश्यक विलंब या गुणवत्ता में लापरवाही बरती जा रही है, उन सड़कों की जाँच 15 दिनों के भीतर कर प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित हों।सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में डॉक्टर, एनएम व सीएचओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय एवं विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए।चांडिल अस्पताल में डायलिसिस केंद्र का संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए,ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके।सभी विद्यालयों में छात्रों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ एवं खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराई जाए।आवासीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत योग्य छात्र-छात्राओं का नामांकन तथा केंद्र में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो यह सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के क्रम मे मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुदूर गाँव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। इसके लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर योग्य लाभुकों को शीघ्र जोड़ा जाए।

यही वही जिला है जहां प्रथम उपायुक्त रही बंदना डाडेल जो संप्रति गृह सचिव, झारखंड सरकार है । उनके कार्यकाल से प्रतिमाह अंतिम सप्ताह योजनाओं का विकास रिपोर्ट अधिकारियों से हस्ताक्षरित कर पत्रकारों को उपलब्ध कराया जाता रहा ।परिणाम यह होता था कि रांची और दिल्ली में बैठी सरकारें जमीनी हकीकत से रूबरू हो जाती थी । परंतु भ्रष्टाचार्यों का एक ऐसा जत्था आया जो चौथे स्तंभ को भी खरीदने में ऐडी चोटी एक कर दिया, फिर पत्रकारों को समाचार देने हेतु एक कर्मचारी की नियुक्ति हुई । नतीजा जहां आज संविधान का चौथा स्तंभ पर जनता का विश्वास टूट रहा है वहीं आज विकास ठप है । भ्रष्टाचारी ,अधिकारी , अभियंता , दलाल , ठेकेदार माला माल है । जनता बेहाल । सच पूछिए तो दिशा का दशा ही बदल कर रख दिया गया आज

बैठक में माननीय खरसावां विधायक दशरथ गागराई, माननीय इचागढ़ विधायक सविता महतो, उपायुक्त नितिश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भाजपा के गुंडों द्वारा की गई तोड़फोड़ और हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ, भाजपा की साज़िश बेनकाब हो गई है: भक्त दास

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर : वोट चोरी का पर्दाफ़ाश करके पूरे भारत में हलचल मचाने वाले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की स्वोट आखिर यात्रास को अब बिहार में भी भारी जनसमर्थन मिल रहा है। इसी संदर्भ में, असहिष्णु भाजपा ने राज्य में हिंसा फैलाने की साज़िश रची है। इसका एक उदाहरण आज बिहार में हुई घटना से पता चलता है। 27 तारीख़ को, भाजपा ने राहुल गांधी की वोट आखिर यात्रा को बाधित करने के लिए बिहार में अपने अल्पसंख्यक विभाग के एक कार्यकर्ता को तैनात किया। उक्त कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ के साथ दुर्व्यवहार किया। सदाकत आश्रम, जो अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के रूप में कार्यरत है, कभी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान था। भाजपा के गुंडों ने आज वहाँ घुसकर व्यापक हिंसा और तोड़फोड़ की। पटना दौरे पर आए ओडिशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने आज पटना में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ने 27 तारीख को दरभंगा में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस समय राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। आम जनता ऐसी घटना के लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा की यह कायराना साजिश आज सबके सामने आ गई है। भाजपा का असली चरित्र और चेहरा आज किसी से छिपा नहीं रह सकता। भाजपा ने सांखयालघु प्रकोष्ठ के एक कार्यकर्ता को ऐसे काम में लगाकर अपना ही चरित्र उजागर कर दिया है। भाजपा के सांखयालघु प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। श्री दास ने कहा कि जहां इस समय देश भर में वोटों की हेराफेरी चर्चा का विषय है और इस मुद्दे पर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं वोटों के मुद्दे से बचने के लिए नए-नए उपाय किए जा रहे हैं। बिहार में भाजपा ने चुनाव आयोग से हाथ मिलाकर SIR के माध्यम से गरीबों और लोगों के मताधिकार को छीनने और सत्ता में वापस आने का ऐसा प्रयास किया है, श्री दास ने कहा। इस तरह की घटना में पुलिस का मौजूद रहना और चुप रहने का नाटक करना सभी को हैरान कर गया है। पुलिस के इस तरह के व्यवहार से आम आदमी भयभीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा के गुंडे ऐसी घटना करके हमारे प्रिय राहुल गांधी और कांग्रेस को नहीं डरा पाएंगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, कांग्रेस इस साल बिहार और पूरे भारत में वोट धांधली के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाएगी। गौरतलब है कि पीसीसी अध्यक्ष श्रीयुक्त दास राहुल गांधी के साथ वोट आखिर यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार आ रहे हैं।

पत्नी से झगड़े के बाद मिली पुलवामा में तैनात सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की लाश : जांच शुरू

सुनील बाजपेई

कानपुर। पत्नी से झगड़ा होने के बाद घर से निकले पुलवामा में तैनात सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर की लाश सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उसी की कार से बरामद की गई है। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7 बजे पार्किंग संचालक ने उनकी डेडबॉडी देखी। इसने घटना की जानकारी जीआरपी को दी। जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंची जीआरपी और फोरेंसिक टीम ने कार की जांच कर ने के साथ ही शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर उत्तराखंड के रहने वाले थे। उनकी तैनाती पुलवामा में थी।

जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ निवासी निर्मल उपाध्याय (38) सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। निर्मल की शादी 17 नवंबर 2023 को साकेत नगर निवासी राशि के साथ हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस राशि ने बताया करीब 12 दिन पहले निर्मल उपाध्याय मेडिकल लीव पर कानपुर आए थे। देर रात शराब पीने के बाद हमारा आपस में झगड़ा हो गया। मेरे साथ मारपीट की। मैंने इसकी शिकायत किदवई नगर पुलिस से कर दी। इसी के बाद वह सुबह करीब 7 बजे वह बिना बताए घर से किराएदार संजय चौहान के साथ कार से चले गए। इसी के बाद उनकी लाश कार से बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है।

कोर्ट के आंख में धूल झोंकने पर जल संसाधन विभाग के अभियंता , सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया जूर्माना

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। झारखंड में अभियंत्रण विभाग कैसे चलता है यह जगजाहिर है । किसी का तालाब उजाड़ दो किसी का फसल बर्बाद कर दो ये बड़े अभियंता , अधिकारी निरीह कर्मचारियों पर किस कदर हावी रहते यहां तक की कोर्ट को आदेश अवमानना करने पीछे नहीं हटते । जिसके कारण आज झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के शीर्ष अधिकारियों पर अदालत की अवमानना में 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार, मुख्य अभियंता जमील अख्तर, अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार और कार्यपालक अभियंता रंजीत कुजूर को जुर्माना रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने का निर्देश दिया. यह राशि बाद में झालसा को स्थानांतरित होगी. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 12 सितंबर तय की. साथ ही कहा कि तय तिथि तक राशि जमा नहीं की गई तो सभी अधिकारियों को कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा. इस संबंध में लखन प्रसाद यादव ने अवमानना याचिका दायर की है. प्रार्थी को क्लास-श्री कर्मचारी के रूप में काम करने की अवधि का वेतन देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रख चार हफ्ते में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था.

22 अगस्त को प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विभाग ने सिर्फ 11,87,230 रुपये का ही भुगतान किया, जबकि एक लाख का भुगतान गलत ढंग से दिखाकर शपथपत्र भी दाखिल कर दिया गया. अदालत ने इसे गुमराह करने की कोशिश माना. सुनवाई के दौरान शनिवार को अदालत में हाजिर सभी अधिकारियों ने कोर्ट से माफी मांगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी से बात खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन है.

छात्र, युवा बीजद संगठन नेता में असंतोष

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : वरिष्ठों के बाद अब युवा और छात्र अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बीजद के बाहरी संगठन में असंतोष गहरा हो गया है। छात्र अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह स्थानीय मंडल में छात्र नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला, वहीं सरे शंखभवन में युवा नेताओं ने वरिष्ठों को घेर लिया।जानकारी के अनुसार, पिछले मंगलवार को बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने छात्र अध्यक्ष के रूप में इप्सिता साहू के नाम की घोषणा की। पार्टी के कई छात्र नेता इसे स्वीकार नहीं कर सके। इसी मुद्दे को केंद्र में रखते हुए कई छात्र नेता शुक्रवार को खंडगिरी के पास एक मंडप में एकत्र हुए। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि जिनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है, उन्हें पद क्यों दिए गए। यह निर्णय लिया गया कि यदि निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो छात्र नेता भविष्य में किसी भी कॉलेज, विश्वविद्यालय और आंदोलन में सहयोग नहीं करेंगे। इसके बाद मिले छात्र नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय दासबर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी नाराजगी जताई। संजय ने कहा कि वह पार्टी अध्यक्ष से इस मामले पर चर्चा करेंगे और उन्हें सूचित करेंगे। गौरतलब है कि बीजद में शामिल होने वाले बताए जा रहे अधिकांश 'वरिष्ठ' बीजू जनता दल नेता पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं जीते थे।

जानकारी है कि छात्र नेता शनिवार को उन तथाकथित वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और उनसे नए अध्यक्ष के चयन के बारे में सवाल करेंगे। युवा नेताओं ने शंख भवन में प्रवेश किया और सवाल किया कि किसके निर्देश पर ऐसा निर्णय लिया गया। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता देवी प्रसाद मिश्रा ने असंतुष्ट युवा नेताओं की एक बैठक बुलाई। बैठक में युवा नेताओं ने भारी हंगामा किया। शाम 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक, युवा नेताओं ने अध्यक्ष चुनने के फैसले को लेकर बहस की। इस समय, देवी मिश्रा ने कहा कि उन्हें उक्त निर्णय के बारे में पता नहीं था। यह जवाब सुनकर, युवा नेता उत्तेजित हो गए और पलटकर पूछा, अगर उन्हें फैसले के बारे में पता नहीं था, तो वे यहां क्यों बैठे हैं। युवा नेताओं ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया कि अगर फैसला नहीं बदला गया तो कोई भी पार्टी के साथ नहीं रहेगा। उन्होंने यह कहकर चेतावनी दी कि अगर वे सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाते हैं तो वे नहीं जाएंगे। उन्होंने देवी मिश्रा से यह भी कहा कि जिसने भी बीजद युवा और छात्र अध्यक्ष का चयन किया है, जिसने निर्णय लिया है, जब तक उन्हें यहां नहीं बुलाया जाता, वे नहीं जाएंगे। चूंकि देवी ने कहा कि नवीन पार्टी के फैसले लेते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, हमें पार्टी अध्यक्ष के पास ले चलो। कई युवा नेताओं ने बताया है कि प्रेस में खबर लिखे जाने तक स्थिति अभी भी अनसुलझी है।

अमृतसर नगर निगम के मेयर जतिंदर सिंह मोती भाटिया जन्माष्टमी के अवसर पर महंत सुखदेव नंद जी के आश्रम पहुंचे

अमृतसर (साहिल बेरी)

बीते कल अमृतसर नगर निगम के आम आदमी पार्टी के मेयर श्री जतिंदर सिंह भाटिया ने पार्षद श्री जरनैल सिंह ढोट के साथ भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर महंत सुखदेव नंद जी के आश्रम में पहुंचकर श्रद्धा के साथ हाज़िरी भरी।

इस मौके पर मेयर भाटिया ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने समाज को प्रेम, सच्चाई, सेवा और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने आगे कहा कि महंत सुखदेव नंद जी हर वर्ष जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर स्वामी जी द्वारा कृष्ण भगवान की स्तुति में कथा का आयोजन किया जाता है तथा भक्तजन भजनों का गायन करते हैं।

आश्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर जन्माष्टमी को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया।

सरायकेला जिले में भी नौकरी के नाम पर ठगी , 90 युवक- युवतियों को पुलिस ने कराया मुक्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

सरायकेला , सब जानते कि झारखंड का सर्वाधिक औधोगिक क्षेत्र परिपूर्ण जिला सरायकेला है तो नौकरी पाने की लालसा लिए युवा खींचे चले आते हैं । पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और छोटा गोविंदपुर के बाद सरायकेला खरसावां जिले में भी नौकरी नाम पर ठगी के शिकार घटना उजागर हुई है . अब कपाली में भी अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी का सपना दिखाकर ठगी करने वाली मार्केटिंग कंपनी का पर्दाफाश हुआ है. गुरुवार को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कंपनी के चार पदाधिकारियों को हिरासत में लिया और करीब 80 से 90 युवक-युवतियों को मुक्त कराया. गिरफ्तार पदाधिकारियों में बेगूसराय निवासी कुंदन कुमार, जनक कुमार, बीरेंद्र कुमार और अमित कुमार शामिल हैं.किसी कुंदन कुमार इसका सुत्रधार रहा .

स्थानीय निवासी संजय यादव ने बताया कि दो दिन पहले राजस्थान का एक युवक उनके पास पहुंचा था. उसने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 35 हजार रुपये ऐंठ लिये गये हैं और अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह और लोगों को इसमें जोड़े. मना करने पर मारपीट की जाती है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोग कंपनी के दफ्तर पहुंचे. वहां मौजूद युवक-युवतियों ने भी ठगी की पूरी कहानी बतायी. इसके बाद हंगामा हुआ और कपाली पुलिस को सूचना दी गयी।

नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मेयर भाटिया ने खिलाड़ियों का किया सम्मान

अमृतसर 30 अगस्त (साहिल बेरी)

नगर निगम अमृतसर के आम आदमी पार्टी के मेयर जतिंदर सिंह भाटिया मास्टर एथलेटिक्स स्पोर्ट्स क्लब अमृतसर द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने क्लब के एथलीटों को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार और सम्मान-पत्र देकर सम्मानित किया।

मेयर भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें खेलों से जुड़ना चाहिए। खेलों से न सिर्फ शरीर, बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है और युवा गलत राहों से दूर रहते हैं।

उन्होंने कहा कि मास्टर एथलेटिक्स स्पोर्ट्स क्लब नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मेयर भाटिया ने यह भी कहा कि नगर निगम की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और खेल मैदानों को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि युवाओं को अच्छी सुविधाएं मिल सकें।

आईएमए अमृतसर ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग को 1000 प्राथमिक चिकित्सा किट दान कीं

अमृतसर, 30 अगस्त (साहिल बेरी)

आईएमए अमृतसर ने राज्य अध्यक्ष (निर्वाचित) डॉ. आर.एस. सेठी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग अमृतसर को 1000 प्राथमिक चिकित्सा किट दान कीं। इस अवसर पर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने बताया कि इन किटों का उपयोग बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया जाएगा और इन किटों के माध्यम से कई अनमोल जानें बचाई जा सकेंगी। इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष (निर्वाचित) डॉ. आर.एस. सेठी और ज़िला अध्यक्ष डॉ. रूपिंदर कौर ने कहा कि आईएमए स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा है और आम लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है।

उन्होंने कहा कि आईएमए पहले भी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करता रहा है और भविष्य में भी लोगों की मदद में अपना योगदान देता रहेगा। इस अवसर पर आईएमए अमृतसर की अध्यक्ष डॉ. रूपिंदर कौर और सचिव डॉ. गुरविंदर सिंह सहित आईएमए के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023